A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 05 फरवरी, 2026
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 155, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2
सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

यूएस ट्रेड डील : भारत की कूटनीतिक बिसात का सफल नतीजा

नीरज कुमार दुबे

जयशंकर की यात्रा सात महीने बाद उनकी पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा है। पिछली यात्रा उस समय हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की अमेरिका यात्रा ऐसे समय हो रही है जब वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा और व्यापारिक खींचतान एक-दूसरे में उलझ चुकी हैं। जयशंकर की यह यात्रा आपूर्ति श्रृंखला, दुर्लभ खनिज, रक्षा सहयोग और व्यापार समझौते पर नए संतुलन की तलाश है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो की पहल पर आयोजित महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में जयशंकर की भागीदारी इस बात का संकेत है कि आने वाले दशक की शक्ति राजनीति खनिज, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा के इर्द गिर्द घूमेगी।

इस यात्रा का पहला स्पष्ट लक्ष्य महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब यह समझ चुकी हैं कि दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता केवल आर्थिक विषय नहीं बल्कि सामरिक प्रश्न है। चीन जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की मुहिम में भारत को एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। भारत की खनिज क्षमता, विशाल बाजार और तकनीकी मांग उसे इस खेल का केन्द्रीय खिलाड़ी बनाती है।

जयशंकर की यह यात्रा सात महीने बाद उनकी पहली द्विपक्षीय अमेरिका यात्रा है। पिछली यात्रा उस समय हुई थी जब अमेरिका ने भारत पर कड़े शुल्क नहीं लगाए थे। इन महीनों में बहुत कुछ बदल गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद शुल्क को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क और रूस से तेल खरीद पर दंडात्मक शुल्क ने संबंधों में कड़वाहट घोली। अब संकेत मिल रहे हैं कि वाशिंगटन नरमी दिखा सकता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि रूस से तेल खरीद घटने पर अतिरिक्त शुल्क हटाने का रास्ता है। साथ ही वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करने की अनुमति का संदेश भी दिया गया है। यह सब केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर सौदेबाजी के पत्ते हैं।

दिलचस्प यह है कि इसी बीच भारत ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौता पूरा कर लिया। इसने अमेरिका को यह संदेश दिया कि नई दिल्ली विकल्प तलाशने में सक्षम है। अटलांटिक परिषद से जुड़े विशेषज्ञ मार्क लिंस्काट का आकलन है कि भारत यूरोप समझौता अमेरिका भारत व्यापार वार्ता को तेज कर सकता है। साफ है कि वाशिंगटन भारत को खोना नहीं चाहता। वैसे भी भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व की हालिया बातचीत और सार्वजनिक बयानों से यह आभास भी मजबूत हो रहा है कि दोनों देश लंबित व्यापार समझौते को अब अधिक देर तक टालना नहीं चाहते। पिछले महीनों में फोन पर हुई वार्ताओं, मंत्रिस्तरीय संपर्क और समान हितों पर दिए गए जोर से यह संकेत मिलते हैं कि माहौल को जानबूझकर सकारात्मक बनाया जा रहा है। ऐसे में जयशंकर की अमेरिका यात्रा को केवल खनिज या सामरिक चर्चा तक सीमित नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे संभावित व्यापार समझौते की राह साफ करने वाली पहल के रूप में भी समझा जा रहा है। कूटनीतिक गलियारों में यह धारणा बन रही है कि यदि इस यात्रा में मुख्य अड़चनों पर सहमति का रास्ता निकलता है तो यह आगे की औपचारिक वार्ता के लिए हरी झंडी जैसा होगा, जिसके बाद मोदी सरकार अंतिम राजनीतिक स्वीकृति देकर समझौते पर मुहर लगा सकती है। यानी यह दौरा भविष्य के बड़े आर्थिक फैसले की भूमिका भी लिख सकता है।

हम आपको यह भी बता दें कि अपनी यात्रा से पहले जयशंकर ने भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। उनके साथ अमेरिकी संसद के सदस्य जिमी पैट्रोनिस, माइक रोजर्स और एडम स्मिथ भी मौजूद रहे। बातचीत में व्यापार, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, हिंद प्रशांत क्षेत्र और यूक्रेन संघर्ष जैसे विषय शामिल रहे। यह केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि जमीन तैयार करने वाली बातचीत थी। गोर ने भारत को अमेरिका का अहम भागीदार बताया और साझा सामरिक हितों पर जोर दिया। साथ ही अमेरिकी संसदीय दल की जनवरी में नई दिल्ली यात्रा भी रक्षा तकनीक सहयोग, सह उत्पादन और सह विकास पर केंद्रित रही। संदेश साफ है कि रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधों की रीढ़ बन सकता है।

अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत के केंद्रीय बजट की घोषणाओं से जोड़कर देखिये। मोदी सरकार ने ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में दुर्लभ खनिज गलियारे बनाने का प्रस्ताव रखा है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और निर्माण को बढ़ावा देने की योजना सीधे उसी दिशा में जाती है जिस पर अमेरिका और उसके सहयोगी काम कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर अभियान के लिए ये खनिज अनिवार्य हैं। बैटरी भंडारण के लिए लिथियम आयन कोश निर्माण, सौर कांच के लिए सोडियम एंटिमोनेट, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आयातित सामान पर मूल शुल्क छूट, मिश्रित सीएनजी पर उत्पाद शुल्क गणना से जैव गैस को बाहर रखना और बैटरी भंडारण परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर सहायता को पांच गुना बढ़ाना दिखाता है कि भारत ऊर्जा और प्रौद्योगिकी की नई दौड़ के लिए तैयारी कर रहा है। 2030 तक पांच सौ गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा और 2047 तक सौ गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य भारत की नई सामरिक दिशा है। निजी भागीदारी खोलने वाला परमाणु ऊर्जा कानून भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

सच यह है कि दुनिया नए शीत युद्ध जैसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां गोलियों से ज्यादा खनिज, चिप और ऊर्जा की आपूर्ति श्रृंखला ताकत तय करेगी। जयशंकर की यात्रा को केवल कूटनीतिक दौरा समझना भूल होगी। यह भारत की बहुस्तरीय चाल है। एक ओर अमेरिका से तनाव घटाना, दूसरी ओर अपने हितों पर अडिग रहना, और साथ साथ यूरोप, रूस तथा अन्य साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना आसान नहीं। पर भारत अब रक्षात्मक नहीं, सौदेबाज की मुद्रा में दिख रहा है।

अमेरिका को भी समझना होगा कि शुल्क की लाठी से साझेदारी नहीं चलती। यदि वह भारत को सचमुच चीन का विकल्प बनाना चाहता है तो भरोसा, प्रौद्योगिकी साझेदारी और बाजार पहुंच देनी होगी। भारत के लिए भी संदेश साफ है कि आत्मनिर्भर खनिज और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए बिना कोई सामरिक स्वायत्तता संभव नहीं।

बहरहाल, जयशंकर की कूटनीति की खासियत यही है कि वे मुस्कान के साथ कठोर संदेश देते हैं। अब देखना यह है कि वाशिंगटन इस संकेत को कितना समझता है। नई दिल्ली ने खेल समझ लिया है और चाल चल दी है।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

एसआईआर पर ममता, ईसी बंगाल को निशाना बना रहा

- कोर्ट से कहा- नाम मिसमैच पर दिए नोटिस वापस लिए जाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) मामले पर सुनवाई की। जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वकीलों के साथ मौजूद रहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के निशाने पर है। जो काम 2 साल में होना था, उसे 3 महीने में करवाया जा रहा है। सुनवाई के बाद सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि असली लोग चुनावी सूची में बने रहने चाहिए। ममता की याचिका पर बेंच ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से 9 फरवरी तक जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखीं। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं।

संसद के बाद अब स्पीकर के ऑफिस में हुआ हंगामा

- विपक्ष और बीजेपी सांसदों में बहस, महिला सांसदों ने संभाला मोर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में विपत्र और बीजेपी सांसदों के बीच बहस हुई है। ऑफिस का जो वीडियो सामने आया है इसमें विपक्ष की महिला सांसद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेण रिजिजू से कुछ कहती नजर आ रही हैं। वहीं, लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार और कांग्रेस पर लिखी किताबें और नोट्स दिखाए। उन्होंने कहा इन किताबों में गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार की मक्कारी, गद्दारी,भ्रष्टाचार और अय्याशी का जिक्र है। निशिकांत की कोट की गई किताबों में एडविना एंड नेहरू,रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एज,द रेड साड़ी का जिक्र है।

भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में अमेरिका से टैरिफ डील पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि डील ऐतिहासिक है। भारत के कृषि और खाद्य क्षेत्र का पूरा ध्यान रखा गया है। यह डील भारत के विकास में बेहद फायदेमंद होगी। गोयल के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। विपक्ष ने 'राहुल गांधी को बोलने दो', नरेंद्र मोदी–सरेंडर मोदी और 'डरता है डरता है नरेंद्र मोदी डरता है' के नारे लगाए। विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा को दोपह 2 बजे तक स्थगित किय गया।

पीएम मोदी जैसी कार में सवार होंगे नीतिश कुमार

- एके-47 की गोलियां चले या दागे जाएं रॉकेट, सेफ रहेंगे सीएम

पटना (एजेंसी)। एके–47 की गोलियां हों या रॉकेट लॉन्चर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार की नई कार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सीएम नई बुलेटप्रूफ रेंज रोवर गाड़ी से चलेंगे। ऐसी गाड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी चलते हैं। सीएम के काफिले के लिए बिहार सरकार जल्द 4 नई गाड़ियां खरीदने वाली है। इसकी शुरुआती कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। रेंज रोवर गाड़ी का मॉडल क्या है? इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। मॉडल और बुलेट प्रूफिंग के लेवल के अनुसार लागत बढ़ सकती है। पीएम जिस रेंज रोवर की सवारी करते हैं वह 10 करोड़ से अधिक की है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार बुलेटप्रूफ कार इस्तेमाल करते हैं। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कई और राज्यों के सीएम भी बुलेटप्रूफ गाड़ियों से चलते हैं।

शरद की सुबह

ख़ंजर से करो बात न
तलवार से पूछो
मैं क़त्ल हुआ कैसे
मेरे यार से पूछो

फ़र्ज़ अपना मसीहा ने
अदा कर दिया लेकिन
किस तरह कटी रात
ये बीमार से पूछो

कुछ भूल हुई है तो
सजा भी कोई होगी
सब कुछ मैं बता दूँगा
ज़रा प्यार से पूछो

आँखों ने तो चुप रह के
भी रूदाद सुना दी
क्यूँ खुल न सके ये
लब–ए–इज़हार से पूछो

रौनक़ है मिरे घर में तसव्वुर
ही से जिस के
वो कौन था 'राही'
दर–ओ–दीवार से पूछो।

– सईद राही

सीएम किसान कल्याण योजना 14वीं किस्त

शिवरात्रि से पहले 81 लाख किसानों को मिल सकती है 2000 रुपये की सौगात

भोपाल (नप्र)। सीएम किसान सम्मान निधि कब आएगी? मध्य प्रदेश के 81 लाख किसानों को जिस एक सवाल के जवाब का इंतजार था, उस पर एक जरूरी अपडेट सामने आई है। नवंबर महीने से प्रदेश के किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त के रूप में 2000 रुपये खाते में आने की बाट जोह रहे हैं। जानकारी मिली है कि इस योजना की 14वीं किस्त 15 फरवरी से पहले जारी की जा सकती है। 15 फरवरी को शिवरात्रि का त्योहार है। इससे पहले किसानों को सौगात मिल सकती है।

अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त जारी करने की तैयारी लगभग पूरी हो गई हैं। 18 फरवरी को मध्य प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। अनुमान है कि 15 फरवरी से पहले यह कार्यक्रम हो सकता है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक मुहर लगना अभी बाकी है। सटीक तारीख को लेकर आधिकारिक सूचना अभी नहीं मिली है।

फरवरी में किसानों को मिल सकती है दोगुनी खुशी– इस तरह से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए फरवरी का महीना काफी खास साबित हो सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त भी फरवरी में ही आनी है। अगर इसमें देरी नहीं होती है और मध्य प्रदेश सरकार भी सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त जारी कर देती है तो उनके खाते में 2 नहीं 4000 रुपये आएंगे। पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि 2000 रुपये जल्द ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का लंबा इंतजार

मध्य प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को ही मिल गई थी। लेकिन इसे बीते 3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं हुई है। जबकि पिछली बार पीएम किसान का पैसा ट्रांसफर होने के कुछ ही दिनों बाद ही पैसा मिल गया था।

सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा उन किसानों को मिलता है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं। हालांकि केंद्र सरकार की इस योजना से 32 लाख के करीब नाम काटे गए हैं। मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें तो सीएम किसान की पिछली किस्त 82 लाख से ज्यादा किसानों में आई थी, जबकि पीएम किसान की 22वीं किस्त 81,91,274 किसानों के खाते में आई थी। आप अपना भी नाम लिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके लिए सारा पोर्टल पर जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं।

बोत्सवाना से मध्यप्रदेश आएंगे 8 चीते : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय वन मंत्री यादव से की दिल्ली में भेंट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्य जीव संरक्षण की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठा रही है। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की बसाहट के बाद अब असम का जंगली भैंसा भी मध्यप्रदेश के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता दिखाई देगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने असम से जंगली भैंसा मध्यप्रदेश लाने की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री यादव से आवश्यक सहयोग और व्यवस्थाओं पर भी विस्तृत रूप से बात की है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन्य जीव संरक्षण और जैव-विविधता संवर्धन के लिए केंद्र सरकार के सहयोग के लिये आभार माना केंद्रीय मंत्री श्री यादव ने प्रदेश के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

राहुल ने नरवणे की किताब दिखाई, बोले-पीएम को दूंगा

- केंद्रीय मंत्री को गद्दार बताया,बिट्टू ने कहा-देश के दुश्मनों से लेना-देना नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। आर्मी चीफ एमएम नरवणे की जिस किताब को लेकर संसद में दो दिन से हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी बुधवार को वही किताब लेकर संसद पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आज पीएम आए तो उन्हें यह किताब दूंगा। राहुल ने किताब का वह पेज खोलकर दिखाया, जिसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से कहा था- जो उचित समझो वह करो!। राहुल ने कहा कि सरकार और रक्षा मंत्री कह रहे है कि किताब का अस्तित्व नहीं है। देखिए यह रही किताब। राहुल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आज लोकसभा में आने की हिम्मत करेंगे। अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो मैं खुद जाकर उन्हें यह किताब सौंपूंगा, ताकि वे इसे पढ़ सकें और देश को इसके बारे में पता चल सके। लोकसभा में दो दिन से पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक पर हंगामा हो रहा है। इसके चलते कई बार सदन स्थगित हो चुका है। राहुल इस किताब के अंश लोकसभा में पढ़ना चाहते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने इसकी इजाजत नहीं दी है। इधर, कांग्रेस के कुछ सांसदों ने बजट सत्र के छठे दिन संसद के मकर द्वार के पास प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल ने बिट्टू को गद्दार कहा।

बिट्टू ने दो साल पहले राहुल को गद्दार कहा था–यह पहली बार नहीं है जब रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी के बीच बयानबाजी देखने को मिली है। सितंबर 2024 में बिट्टू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। बिट्टू ने अमेरिका में सिखों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने सिखों को बांटने की कोशिश की है।

- रियल एस्टेट कारोबारी की शूटरों से हत्या करवाई थी, हुलिया बदलने में माहिर था

काशी में सुपारी किलर बनारसी यादव एनकाउंटर में ढेर

वाराणसी (एजेंसी)। वाराणसी में सुपारी लेकर रियल एस्टेट कारोबारी की शूटरों से हत्या करवाने वाला बनारसी यादव एनकाउंटर में मारा गया। मंगलवार देर रात इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने उसकी घेराबंदी की। इंस्पेक्टर ने उसे सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने फायरिंग कर दी। बदमाश की गोली से दो सिपाही बाल-बाल बचे। इसके बाद एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करते हुए पुलिसवाले उसकी ओर बढ़े। बनारसी और जवानों के बीच आमने-सामने 5 राउंड फायरिंग हुई। दो गोलियां बनारसी को लगीं। वह गिर पड़ा। घायलावस्था में उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बनारसी को मृत घोषित कर दिया। बनारसी के पास से दो पिस्टल और कारतूस मिले हैं। एनकाउंटर चौबेपुर रोड पर हुआ। बनारसी गाजीपुर के करंडा का रहने वाला था। उस पर 10 हत्याओं समेत 21 मुकदमे वाराणसी, गाजीपुर सहित कई जिलों में दर्ज थे। पांच महीने पहले गाजीपुर के ही रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर योगेंद्र ने 50 करोड़ की जमीन के लिए कोलोनाइजर महेंद्र गौतम की हत्या करवाई थी। उसने बनारसी यादव को 5 लाख की सुपारी दी थी। इसके बाद उसने फौजी अरविंद यादव और विशाल समेत 3 बदमाशों को हायर किया। 21 अगस्त 2025 को बदमाशों ने ऑफिस जा रहे कोलोनाइजर को दिनदहाड़े गोली मार दी थी। कोलोनाइजर की हत्या के मामले में पुलिस ने बनारसी पर 1 लाख का इनाम घोषित किया था।

सुबह सवेरे
भोपाल ■ गुरुवार, 05 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

डीआरडीओ ने किया नई तकनीक का सफल टेस्ट

लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद मिलेगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने मंगलवार को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (एसएफडीआर) तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास यह आधुनिक तकनीक है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह टेस्ट ओडिशा के तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) में किया गया। यह तकनीक लंबी दूरी की हवा

से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद करती है। इस तकनीक से संभावित विरोधियों के मुकाबले रणनीतिक बढ़त मिलती है। परीक्षण के दौरान सभी प्रमुख उप-प्रणालियों ने अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन किया। इनमें बिना नोजल वाला बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर शामिल थे। सिस्टम को पहले ग्राउंड बूस्टर मोटर की मदद से निर्धारित मैक संख्या तक पहुंचाया गया, जिसके बाद एसएफडीआर प्रणाली ने सफलतापूर्वक काम किया। पूरे परीक्षण की निगरानी और पुष्टि आईटीआर, चांदीपुर की ओर से बंगाल की खाड़ी के तट पर तैनात कई ट्रैकिंग उपकरणों से प्राप्त उड़ान आंकड़ों के जरिए की गई। टेस्ट के दौरान डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद रहे। इनमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हाई एनर्जी मटीरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के अधिकारी शामिल हैं।

घाटी के उधमपुर में जैश के दो आतंकी ढेर

- गुफा में छिपे थे दोनों, सुरक्षा बलों ग्रेनेड से उड़ाया

उधमपुर (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने गुफा में छिपे जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के दो आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सेना के अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जैश के शीर्ष कमांडर सहित दो आतंकवादी मुठभेड़ में मारे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, शाम करीब साढ़े सात बजे आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद

इलाके में फिर से गोलीबारी और जोरदार धमाके हुए। उन्होंने बताया कि इसके बाद घेराबंदी को और मजबूत करने के लिए पैराट्रूपर्स और श्वान दस्ते सहित सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया था। यह 15 दिसंबर के बाद उधमपुर में दूसरी मुठभेड़ थी, जब सौन गांव में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। हालांकि, घने जंगल और अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी भागने में कामयाब रहे थे। जनवरी में कठुआ जिले में तीन और किश्तवाड़ के चतरू वन क्षेत्र में चार मुठभेड़ें हुईं जिनके परिणामस्वरूप कठुआ में जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान को ढेर किया गया और किश्तवाड़ में एक पैराट्रूपर शहीद हो गया। ये मुठभेड़ जम्मू क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए चल रहा है।

जाति-धर्म पर राजनीति करने वालों की बल्ले-बल्ले!

- हाई कोर्ट ने कहा- रोक नहीं लगा सकता चुनाव आयोग

लखनऊ (एजेंसी)। भारत निर्वाचन आयोग जाति और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों या नेताओं को चुनाव लड़ने से रोक नहीं लगा सकता है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका पर यह महत्वपूर्ण फैसला आया है। हाई कोर्ट में जातीय रैली के को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए साफ किया है कि वर्तमान कानून के तहत किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को केवल इस आधार पर चुनाव लड़ने से पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि वह जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। याचिका पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि यह विषय विधायिका से संबंधित है। विधायिक इस संबंध में कानून बनाए। चुनाव आयोग भी किसी भी राजनीतिक दल

का पंजीकरण जाति या धर्म पर आधारित राजनीति करने के नाम पर समाप्त नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की ओर से वर्ष 2013 में दाखिल जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट की पीठ नेयाचिका पर विस्तृत निर्णय पारित करते हुए कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8-ए ही एकमात्र प्रावधान है। इसके तहत चुनावी कदाचार के मामलों में अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसमें भी यह तभी लागू हो सकता है जब संबंधित व्यक्ति को दोषसिद्ध करार दिया जा चुका हो।

शिक्षा-परिवार को बताया महत्वपूर्ण

हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसले में परिवार और शिक्षा प्रणाली में सही मूल्यों के संचार को जरूरी बताया। कोर्ट ने कहा कि इससे ही भावी नागरिक संविधान की भावना, विशेषकर अनुच्छेद 51-ए(ई) में निहित भ्रातृत्व और सामाजिक समरसता के आदर्शों को आत्मसात कर सकता है। हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनों का निर्माण और उनका प्रभावी क्रियान्वयन अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। हालांकि, सब कुछ कानून से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति, समाज, कार्यपालिका और विधायिका का सामूहिक प्रयास आवश्यक है।

यूपी में प्रतिबंध पर भी निर्देश

यूपी में जातीय रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 21 सितंबर 2025 को इससे संबंधित शासनादेश जारी किया था। कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई और फैसले के क्रम में इसे देखा। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आयोजित होने वाली जातीय रैलियों से समाज में जातीय संघर्ष बढ़ता है। यह लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। इसलिए, प्रदेश में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर सरकार के इस आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, तो वे पर्याप्त आंकड़ों के साथ याचिका दायर कर सकते हैं।

भारत को बांग्लादेश बनाने के मंसूबे पर रेलवे डालेगा मवाद

- 24 मीटर गहरी सुरंग में दफन होगा शरजील इमाम का दिमाग

भारत के चिकननेक कॉरिडोर में अंडरग्राउंड सुरंग में गुजरेगी ट्रेन

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने बदलते जियो पॉलिटिक्स और देश में बैठे गद्दारों से निपटने के लिए माकूल नीतियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देश के पूरे भूभाग को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाले पश्चिम बंगाल के चिकननेक कॉरिडोर को हमेशा के लिए सुरक्षित बनाने की योजना तैयार की गई है।

बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन पड़ोसियों की इस चिकननेक कॉरिडोर पर गलत नजर तो रही ही है, देश में बैठे दुश्मनों का भी मंसूबा बहुत खतरनाक है।

- 20 से 24 मीटर गहराई में बनेगी अंडरग्राउंड लाइन

अंडरग्राउंड रेलवे सुरंग आमतौर पर 20 से 40 मीटर गहराई में बनाई जाती है। नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे इस स्ट्रैटजिक अंडरग्राउंड रेलवे को जमीन से 20 से 24 मीटर की गहराई में बनाएगा, ताकि देश के दुश्मनों का दिमाग भी वहीं पहुंचते-पहुंचते ठंडा पड़ जाए। एनएफआई के जनरल मैनेजर चेतन कुमार श्रीवास्तव का कहना है सुरक्षा के नजरिए से अंडरग्राउंड स्ट्रेच महत्वपूर्ण है। यह अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क पश्चिम बंगाल में टिन माइल हाट से रंगापानी स्टेशनों के बीच बनेगा। एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल के बागडोगरा को जोड़ेगा, जिसे देश के एयर डिफेंस मेकेनिज्म के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है।

- **पूर्वोत्तर तक पहुंचने का एकमात्र जमीनी गलियारा-** जबसे बांग्लादेश में शेख हसीना को पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों ने जबरन सत्ता से बेदखल किया और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार को कमान मिली है, भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर देश के दुश्मनों की भी नजरें गड़ गई हैं। कहने के लिए तो यह जमीन की मात्र 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा संकड़ा गलियारा है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूर्वोत्तर के आठों राज्यों तक पहुंचने का यही एकमात्र जमीनी रास्ता है।
- **चिकननेक कॉरिडोर में बिछेगी अंडरग्राउंड लाइन-** चिकननेक कॉरिडोर की रणनीतिक अहमियत को समझते हुए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस इलाके में न सिर्फ नई वैकल्पिक रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी, बल्कि अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी बिछाने का इंतजाम कर लिया गया है।

ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम

इंदौर में रॉन्ग साइड चलने पर अब दर्ज होगी एफआईआर

भोपाल/इंदौर (नप्र)। शहर में लगातार बिगड़ती जा रही ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन अब और अधिक सख्त कदम उठाने जा रहा है। अब तक रॉन्ग साइड वाहन चलाने या वनवे नियमों का पालन न करने पर केवल चालानी कार्रवाई होती थी। अब ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज की जाएगी। यह

व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तर्ज पर लागू की जा रही है ताकि सड़क हादसों पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं

दरअसल, रॉन्ग साइड वाहन चलाने और वनवे में घुसने की घटनाओं के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। इसी को देखते हुए इंदौर पुलिस ने सख्त रूख अपनाने का निर्णय लिया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण में शहर के 42 घोषित वनवे मार्गों पर यह कार्रवाई लागू की जाएगी। इन मार्गों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब सीधे एफआईआर दर्ज की जाएगी।

अपराध की श्रेणी में आता है रॉन्ग साइड वाहन चलाना

इंदौर पुलिस का कहना है कि नए भारतीय न्याय संहिता के तहत रॉन्ग साइड वाहन चलाना अब आपराधिक श्रेणी में आता है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है और आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग रॉन्ग साइड या लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर दूसरों की जान खतरे में डालते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी ताकि लोग इस तरह के कृत्य न कर सकें।

कई सड़के हैं वनवे घोषित

इंदौर में कई ऐसे इलाके और सड़कें हैं, जिन्हें वनवे घोषित किया गया है लेकिन समय के साथ वहां नियमों का पालन कम हो गया है। इसी को लेकर हाल ही में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने भी पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी।

सुधीर सक्सेना और लीलाधर मंडलोई को आन्ना अख़मातवा अनुवाद सम्मान

मसक्वा। भारत मित्र समाज, मसक्वा द्वारा रूसी साहित्य को भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत करने वाले अनुवादकों के लिए स्थापित वर्ष 2026 का पहला आन्ना अख़मातवा सम्मान जाने माने अनुवादक कवि सुधीर सक्सेना और लीलाधर मंडलोई को संयुक्त रूप से दिया

जाएगा। हिन्दी के कवि सुधीर सक्सेना पिछले पचास साल से रूसी कवियों की रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद कर रहे हैं। इन्होंने ही सबसे पहले हिन्दी में आन्ना अख़मातवा की कविताओं को प्रस्तुत किया था। कवि लीलाधर मंडलोई ने भी हिन्दी में रूसी कविता को पेश करने का ज़रूरी काम किया है। आन्ना अख़मातवा सम्मान की घोषणा करते हुए भारत मित्र समाज, मसक्वा के महासचिव अनिल जनविजय ने बताया कि निर्णायक मण्डल में रूसी भारतविज्ञ अलिक्सान्दर सेंकेविच, कवि ततियाना फ़िलिपवा, कथाकार रमान सेनचिन, कथाकार ज़ख़ार प्रिलेपिन, कवि ईगर सीद और अनिल जनविजय शामिल थे। मूल रूप से हिन्दी के कवि सुधीर सक्सेना के आठ कविता संग्रह और रूसी कविता के अनुवादों की सात किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पुरस्कारों से सम्मानित सुधीर सक्सेना को 1997 में रूस का पुश्किन सम्मान मिला था। लीलाधर मंडलोई भी हिन्दी के वरिष्ठ कवि हैं और 2002 में इन्हें रूस का पुश्किन सम्मान मिल चुका है। आजकल वे रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, भोपाल के विश्वरंग साहित्यिक कार्यक्रम के सहनिदेशक हैं।

मोबाइल गेम की लत

3 बहनों ने दांव पर लगाई जिंदगी

- गाजियाबाद में 9वीं मंजिल से कूदीं, उम्र 12-14-16 साल
- सुसाइड नोट में लिखा-सॉरी मम्मी-पापा

गाजियाबाद (एजेंसी)। गाजियाबाद में तीन सगी बहनों ने नौवीं मंजिल की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक, मंगलवार रात 2 बजे तीनों ने कमरे को अंदर से बंद किया, फिर स्टूल रखकर एक-एक करके बालकनी से छलांग लगा दी। उनकी उम्र करीब 12, 14 और 16 साल है। पिता के मुताबिक, तीनों बेटियों को टास्क-बेस्ड कोरियन लव गेम की लत थी। वे हर वक्त एक साथ रहती थीं। एक साथ नहाती थीं और टॉयलेट जाती थीं। इस कदर गेम की लत थी कि

स्कूल भी छोड़ दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई। इसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। तीनों बहनें जिस कमरे में सोती थीं, वहां पुलिस को एक डायरी मिली है। इसके 18 पन्नों में सुसाइड नोट लिखा मिला।

पिता ने दो शादियां कीं, शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं

तीनों बच्चियों के नाम निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) हैं। पिता चेतन गुर्जर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। वह मूल रूप से दिल्ली के खजूरी के रहने वाले हैं। परिवार में 2 पत्नी, 7 साल का बेटा और चार बच्चियां थीं। साथ में साली भी रहती है। चेतन ने दो शादियां की हैं। पहली पत्नी से बच्चे नहीं होने पर उन्होंने उसकी बहन यानी साली से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से निशिका और प्राची का जन्म हुआ। इसके बाद पहली पत्नी से भी एक बेटी पैदा हुई। फिर दूसरी पत्नी से एक और बेटी-बेटा भी हुए हैं। जिस फ्लैट में परिवार रहता है, उसमें तीन कमरे और एक हॉल है। घटना के वक्त चेतन दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। साली, 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में थे।

सेवानिवृत्ति पश्चात सर्वोच्च प्राथमिकता स्वस्थ जीवन हो : सुभाष मूंदड़ा

भोपाल। सेवानिवृत्ति के बाद हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता स्वास्थ्य की देखभाल होना चाहिए। साथ ही यथासंभव समाज सेवा के लिए भी समय देना चाहिए। यह उदगार रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष मुंदड़ा

ने बैंक ऑफ बड़ौदा रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा व सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप मे व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिंडिकेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक अरुण श्रीवास्तव ने की।

इस आयोजन में अपने जीवन के 85 व 75 वर्ष पूर्ण कर चुके सेवानिवृत्त अधिकारियों का सपत्नीक सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बैंकिंग उद्योग के शीर्ष पद पर रहे दिग्गज विजया बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रेम सेठी, बैंक ऑफ बड़ौदा के भोपाल अंचल के महाप्रबंधक शैलेष पारख, बैंक ऑफ बड़ौदा के ही इंदौर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक, उप महाप्रबंधक शिबाशीष मिश्रा, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय,भोपाल अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी केंद्र के निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महा प्रबंधक डॉ. जवाहर कर्नावट तथा राष्ट्रीय सहायक महासचिव आर. के. मंडल का प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ। स्वागत उद्बोधन एसोशिएशन के अध्यक्ष जी. एन. अग्रवाल ने दिया तथा संगठन के महासचिव सत्यनारायण पालीवाल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम संचालन संतोष मोहन्ती ने एवं आभार प्रदर्शन जैनेन्द्र जैन ने किया।

मोबाइल गेमिंग की लत के शिकार स्टूडेंट ने लगाई फांसी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में मोबाइल गेमिंग की लत के चलते 14 साल के स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। परिजन को आशंका है कि ऑनलाइन गेम में दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए बच्चे ने आत्मघाती कदम उठाया। फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी है।

मामला पिपलानी थाने की श्रीराम कॉलोनी का है। यहां रहने वाले 14 वर्षीय अंश साहू ने सोमवार दोपहर अपने घर में फांसी लगा ली। 8वीं क्लास में पढ़ने वाला अंश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। माता-पिता प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। परिजन ने पुलिस को बताया कि अंश को कुछ दिन से मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग गई थी। इसी बात को लेकर उसे कई बार समझाया गया था। पढ़ाई पर असर पड़ता देख परिवार वालों ने उसका मोबाइल फोन छीनकर रख लिया था। सोमवार को अंश के माता-पिता तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने घर से बाहर गए थे। लौटे तो अंश कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। वे उसे तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पड़ोसियों के अनुसार, अंश शांत स्वभाव का था। हाल के दिनों में वह अकेले रहना पसंद करने लगा था। वहीं, पिपलानी थाना प्रभारी चंद्रिका यादव ने कहा- प्राथमिक तौर पर लग रहा है कि बच्चे ने मोबाइल की लत के कारण ये कदम उठाया।

विश्व कैंसर दिवस: गैस पीड़ित महिलाओं की अपेक्षा गैस पीड़ित पुरुषों में कैंसर की दर ज़्यादा है

भोपाल। आज विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आयोजित पत्रकार वार्ता में सम्भावना ट्रस्ट क्लिनिक के सदस्यों ने यह जानकारी पेश की कि 1984 की यूनियन कार्बाइड हादसे से प्रभावित आबादी में कैंसर की दर, अपीड़ित आबादी की तुलना में लगभग 13 गुना ज़्यादा है। आँकड़ों से यह भी पता चलता है कि गैस पीड़ित महिलाओं की अपेक्षा गैस पीड़ित पुरुषों में कैंसर का दर ज़्यादा है। यह भी देखा गया है कि गैस पीड़ित आबादी में खून, फेफड़े और गले के कैंसर की दर सबसे ज़्यादा है।1996 में स्थापित सम्भावना ट्रस्ट क्लिनिक भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों को मुफ्त इलाज मुहैया कराता है।

क्लिनिक की सामुदायिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण यूनिट के सदस्य राधे लाल नापित ने कहा, हमने 21276 गैस पीड़ितों और 25528 अपीड़ित व्यक्तियों के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जानकारी इकट्ठा की है, जिनकी आय और शिक्षा समान है। कैंसर का आँकड़ा उन सभी लोगों का है जिन्हें 1992 और 2012 के बीच कैंसर का पता चला था। हमारे पास कैंसर वाले लगभग सभी व्यक्तियों के मेडिकल रिकॉर्ड की कॉपी हैं।

फरहत जहाँजो इस और अन्य जानकारी इकट्ठा करने के लिए घर-घर जाने वाली टीम का हिस्सा हैं, ने कहा, हमारा आँकड़ा यह दिखाता है कि, जबकि गैस पीड़ित आबादी में कैंसर की दर प्रति 100,000 पर 1569.84 है, वहीं अपीड़ित आबादी में यह प्रति 100,000 पर 117.52 है। गैस पीड़ित पुरुषों में कैंसर की दर 14.92 गुना ज़्यादा है, जबकि गैस पीड़ित महिलाओ में यह 12.22 गुना ज़्यादा है।

सर्वे टीम के एक अन्य सदस्य चन्द्रशेखर साहू ने बताया कि यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों में कुछ तरह के कैंसर ज़्यादा आम थे। हम पाते हैं कि गैस पीड़ित आबादी में खून के कैंसर की दर अपीड़ित आबादी की तुलना में 21.6 गुना ज़्यादा है। इसी तरह, फेफड़े और गले के कैंसर की दर अपीड़ित आबादी की तुलना में क्रमशः 28.78 और 33.86 गुना ज़्यादा है।

कृषक कल्याण वर्ष में किसानों को मिल रही है वैज्ञानिक कृषि तकनीक की जानकारी

कृषि रथ से किसानों को मिट्टी में मौजूद तत्वों के अनुसार फसल कॉम्बीनेशन की मिल रही जानकारी

भोपाल (नप्र)। कृषक कल्याण वर्ष-2026-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि को आधुनिक तकनीक, परम्परागत ज्ञान और प्राकृतिक संतुलन के साथ नई ऊँचाइयों तक ले जाने तथा अन्नदाता के सम्मान और समग्र उत्थान की दिशा में इस महा अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा किया गया है। बुरहानपुर जिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं संवाद-सत्र के आयोजन के साथ ''कृषि रथ'' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर बुरहानपुर विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस, जनप्रतिनिधि, प्रगतिशील कृषकगण उपस्थित रहे।

कृषि रथ द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पहुंचकर किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, कीट एवं रोग प्रबंधन, फसल विविधिकरण, कृषि को लाभकारी बनाने के उपाय, विभागीय योजना, ई-टोकन उर्वरक वितरण व्यवस्था तथा पराली प्रबंधन संबंधित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। प्रगतिशील किसानों को उत्पादन लागत को कम करने के लिये सही मिट्टी, सही खेती एवं सही फसल का कॉम्बीनेशन की जानकारी भी दी जा रही है।

ग्राम पातोंडा, चिंचाला एवं एमागिर्द में कृषक चौपाल आयोजित

बुरहानपुर जिले में कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पंचायत पातोंडा, चिंचाला एवं एमागिर्द में कृषक चौपाल का आयोजन किया गया। कृषक चौपाल में उर्वरक वितरण की ई-टोकन प्रणाली, प्राकृतिक खेती के आधार जैसे:-जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क को बनाने की विधि की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से मृदा के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों, मिट्टी नमूना लेने की विधि एवं संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग की अनुशंसा करने की सलाह दी गयी। दलहन एवं तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए जायद फसल उड़द और मूंगफली के बारे में बताया गया एवं बुवाई के लिए प्रेरित भी किया गया। बुरहानपुर जिले के विभिन्न ग्रामों में आयोजित हो रही कृषक चौपालों में पराली प्रबंधन सहित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी जानकारी दी जा रही है।

ग्राम बाकड़ी में लगी कृषि चौपाल, योजनाओं की दी जानकारी

कृषक कल्याण वर्ष-2026 अंतर्गत बुरहानपुर जिले के ग्राम बाकड़ी में कृषि रथ पहुंचा। इस दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाकर ग्रामीणों को उन्नत कृषि एवं तकनीकियों की बारीकी से जानकारी दी गयी। ग्रामीणों को जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कीट व रोग प्रबंधन, फसल विविधीकरण, उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उपाय बताये गये। कृषि विभाग द्वारा संचालित कृषि रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहा है। प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिले में समृद्ध किसान से समृद्ध प्रदेश बनाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रत्येक गुरूवार को ''प्राकृतिक हाट बाजार'' आयोजित

बुरहानपुर जिले में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने एवं उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति गुरुवार को महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि उपज मंडी, शनवारा में ''प्राकृतिक हाट बाजार'' का आयोजन किया जा रहा है। हाट बाजार के अवलोकन के दौरान कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है, इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ-साथ सुरक्षित एवं पौष्टिक उत्पाद प्राप्त होते है, अन्य किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने के लिये प्रोत्साहित करें।

अमेरिका-भारत ट्रेड डील, किसानों पर संकट

प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक स्थिति और भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार की चुप्पी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश और प्रदेश में सबसे अधिक पीड़ित और दुखी यदि कोई है तो वह किसान, आम जनता और युवा हैं-जिन्हें केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने पूरी तरह उपेक्षित कर दिया है।

श्री पटवारी ने कहा कि अमेरिका के कृषि मंत्री द्वारा दिया गया हालिया बयान, जिसमें भारत-अमेरिका ट्रेड डील की जानकारी सामने आई है, बेहद चिंताजनक है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर 0 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। इसमें ड्राई फ्रूट्स, फल-सब्ज़ियां, शराब, स्पिरिट, औद्योगिक उत्पाद, रसायन और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। वहीं भारत में उत्पादित कृषि सामग्री जब अमेरिका जाएगी तो उस पर 18 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब अमेरिका का कृषि मंत्री खुलकर बयान दे रहा है, तो भारत के कृषि मंत्री-जो स्वयं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं-इस विषय पर मौन क्यों हैं? यह चुप्पी किसके दबाव में है?

श्री पटवारी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पहले ही आगाह किया था कि यह ट्रेड डील 100त्न भारत के खिलाफ होगी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय दबाव में झुकेंगे। आज यह बात एक बार फिर सत्य साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में किसान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। किसी भी फसल को न तो उचित मूल्य मिल रहा है और न ही एमएसपी पर खरीदी हो रही है। भाजपा सरकार ने खेती को लाभ का धंधा बनाने का वादा किया था, लेकिन आज भारत दुनिया में किसानों की आत्महत्या के मामलों में सबसे ऊपर पहुंचता जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। श्री पटवारी ने कहा कि यदि अमेरिका से सस्ता कृषि उत्पादन 0 प्रतिशत टैक्स पर भारत आएगा, तो देश के किसानों की आमदनी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ किसी भी प्रकार की घात के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और निर्णायक आंदोलन करेगी।

प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए श्री पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने कर्ज़ लेने के मामले में अपने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। चालू वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार अब तक 1 लाख 78 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है और हाल ही में लिए गए 5200 करोड़ रुपये को मिलाकर प्रदेश पर प्रतिदिन लगभग 213 करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार यह तर्क देती है कि कर्ज़ जीडीपी के दायरे में है, लेकिन सच्चाई यह है कि बजट का आकार केवल कर्ज़ लेने के लिए बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश सरकार अब आम जनता से भी कर्ज़ लेने की स्थिति में पहुंच गई है, जो गंभीर आर्थिक दिवालियापन का संकेत है।

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर श्री पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफ ओबीसी हितैषी होने का दिखावा करती है और दूसरी तरफ सरकारी धन से महंगे वकीलों को फीस देकर ओबीसी आरक्षण को रोकने का प्रयास कर रही है। यह पैसा ओबीसी समाज और प्रदेश की जनता का है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मांग करती है कि भाजपा सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे, जिसमें प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सुधार की योजना स्पष्ट हो। कांग्रेस विपक्ष के रूप में सहयोग को तैयार है, लेकिन प्रदेश को अंधेरे में नहीं धकेलने देगी। अंत में श्री पटवारी ने कहा कि जिन मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं-वे मंत्री पद पर रहने के अधिकारी नहीं हैं।

26 मौतों के लिए जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री

32 मौतों के लिए जिम्मेदार मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तत्काल बर्खास्त किया जाए। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव से आग्रह है कि वे पद की गरिमा बनाए रखें, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करें और प्रदेश की जनता को जवाब दें। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जनता की आवाज़ बनकर संघर्ष करती रहेगी।

श्वेत पत्र लाए सरकार, विशेषज्ञों की समिति बनाए

पटवारी ने कहा कि कांग्रेस कई बार मांग कर चुकी है कि मोहन सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इसके लिए अर्थशास्त्रियों की एक समिति बनाई जाए, जिसमें नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी शामिल किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि मध्य प्रदेश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। सरकार किसानों और लाड़ली बहनों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रही है।

कर्ज लेने में शिवराज से आगे निकली मोहन सरकार

जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्ज लेने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 78 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है, यानी रोज़ करीब 213 करोड़ रुपए का कर्ज। पटवारी ने कहा कि सिर्फ एक दिन पहले ही 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। जब इस पर सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार विकास का हवाला देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट का आकार जानबूझकर बड़ा रखा जाता है ताकि ज्यादा कर्ज लिया जा सके। पटवारी ने कहा कि सरकार की हालत इतनी खराब है कि अब सरकारी संस्थानों की बजाय आम जनता से कर्ज लिया जा रहा है। कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जा रही हैं। 13 संपत्तियों को जल्दबाजी में बेचने की तैयारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राजनीतिक अय्याशी और भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को अर्थशास्त्र की समझ नहीं है और वे संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरकार को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है।

'शक्कर जहर होता है, छोड़ो उसको', मिठाई चाप रहे बीजेपी विधायक को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टोका

अशोकनगर (नप्र)। गुना सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों अशोकनगर के दौरे पर हैं। इस दौरान मंगलवार की रात वह चंदेरी पहुंचे। चंदेरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व विधायक डग्गी राजा के घर पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके बाद मलकीत सिंह संधू के घर पर गए, वहां चंदेरी के विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी भी थे। डायनिंग टेबल पर अतिथियों के लिए खाना रखा हुआ था।

मिठाई खाते वक्त टोका- दरअसल, खाने के साथ सभी लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। वहीं, चंदेरी विधायक खा रहे थे। मीठा खाने में जगन्नाथ रघुवंशी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। यह देखकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें टोक दिया था। साथ ही कहा कि शक्कर जहर के समान है। इससे सारी बीमारियां होती हैं। आपको शुगर भी है क्या। विधायक ने जवाब में कहा कि हां, शुगर है। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं शुगर खाना चाहिए। सिंधिया ने विधायक से कहा कि शुगर आपके लिए निषेध है। आप नेचुरल मीठा खा लो, मगर वो मत खाना। शुगर शरीर के पार्ट को एक-एक कर मारता है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि आप शुगर को जिंदगी में जितना कम हो सके लो। वहीं, खाने के लिए मक्के की रोटी और सरसों के साग को मेहमानों के लिए रखा गया था। गौरतलब है कि गुना संसदीय क्षेत्र से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। अपने दौरे के दौरान वह लोगों से मिलते जुलते हैं। साथ ही इस क्षेत्र के लोगों को सौगात भी देते हैं। अशोकनगर में भ्रमण के दौरान उन्होंने युवाओं की शिकायत पर प्ले ग्राउंड से अतिक्रमण हटवाया था।

भोपाल कलेक्ट्रेट के मौजूदा परिसर में ही बनेगी नई बिल्डिंग

कमिश्नर ने पूछा- किस विभाग को कितने स्पेस की जरूरत, जानकारी भी ली

भोपाल (नप्र)। भोपाल कलेक्ट्रेट के मौजूदा परिसर में ही नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। यहां कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न विभागों के कार्यालयों के लिए पांच से छह मंजिला भवन का निर्माण प्रस्तावित है। किस विभाग को कितनी जगह की आवश्यकता होगी, इसे लेकर मंगलवार को संभागायुक्त कार्यालय में संभागायुक्त संजीव सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक ली।

बैठक के दौरान अधिकारियों से उनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और आवश्यक स्पेस की जानकारी ली गई। एक-एक कर सभी विभागों ने अपनी जरूरतों से संभागायुक्त को अवगत कराया।

नए भवन में जिला कलेक्टर कार्यालय, संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस विभाग सहित खाद्य आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा, आबकारी, तहसील, महिला एवं बाल विकास समेत अन्य विभागों के कार्यालय एक ही परिसर में बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि आम नागरिकों को अलग-अलग जगह भटकना न पड़े और एक ही परिसर में उनके काम पूरे हो सकें।

बैठक में नए भवन की संभावित डिजाइन भी प्रस्तुत की गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस मंजिल पर कौन-सा विभाग रहेगा। एडीएम अंकुर मेश्राम ने बताया कि इसी जानकारी के आधार पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा भवन की फाइनल डिजाइन तैयार की जाएगी।

बैठक में पुलिस, खाद्य आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास, जिला जनसंपर्क सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिक भीड़ वाले विभागों को मिलेगा ज्यादा स्पेस- नए भवन में जिन विभागों में लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक जगह दी जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर कार्यालय, तहसील, पुलिस विभाग और लोक सेवा केंद्र शामिल हैं। वहीं, जिन विभागों में आमजन की आवाजाही कम रहती है, उन्हें कम स्पेस आवंटित किया जाएगा, जैसे महिला एवं बाल विकास, जिला शिक्षा, आबकारी और खाद्य विभाग।

प्रोफेसर कॉलोनी में प्रस्तावित भवन निरस्त- पहले कलेक्ट्रेट का नया भवन प्रोफेसर कॉलोनी क्षेत्र में बनाने का प्रस्ताव था, जिसके लिए करीब 13 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। हालांकि जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और पर्यावरणविदों के विरोध के चलते यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। विरोध का कारण पेड़ों की कटाई और छोटे तालाब से सटे क्षेत्र में पर्यावरण एवं जैवविविधता को संभावित नुकसान बताया गया। इसी को देखते हुए शासन-प्रशासन ने मौजूदा कलेक्ट्रेट परिसर में बने पुराने कार्यालयों को हटाकर वहीं बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया है।

पांच से छह मंजिला इमारत का प्रस्ताव सभी प्रमुख विभाग एक ही परिसर में होंगे, अधिक भीड़ वाले विभागों को मिलेगा ज्यादा स्पेस, प्रोफेसर कॉलोनी का प्रस्ताव पर्यावरणीय कारणों से निरस्त हाउसिंग बोर्ड तैयार करेगा अंतिम डिजाइन।

ट्रेन से तस्करी, दो बैग में 311 कछुए मिले

पटना-इंदौर एक्सप्रेस का कोच अटेंडेंट निकला तस्कर, अवैध शराब की तलाश में पहुंची थी आरपीएफ

भोपाल (नप्र)। पटना-इंदौर एक्सप्रेस (19322) के एच-1 कोच का अटेंडेंट कछुआ तस्कर निकला। मंगलवार (3 जनवरी) को तलाशी के दौरान आरपीएफ ने उसके दो बैग से 311 जीवित इंडियन टेंट टर्टल बरामद किए हैं।

आरपीएफ की टीम ट्रेन में अवैध शराब को लेकर सर्चिंग कर रही थी। इस दौरान एएसआई हेमंत कुमार राजपूत और आर. जॉनी कुमार ने अटेंडेंट अजय सिंह राजपूत पिता रामकुमार की संदेह के आधार पर तलाशी ली। उसके पास दो बैग रखे थे, जिनमें छोटे-छोटे जीवित कछुए पाए गए। यह मामला अब सिर्फ बरामदगी तक सीमित

नहीं रह गया है। आरपीएफ अधिकारियों से बातचीत, आरोपी से पूछताछ और इक्केरियम कारोबार से जुड़े लोगों की जानकारी के आधार पर इस मामले में अवैध मुनाफे का बड़ा एंगल सामने आया है। आरपीएफ के मुताबिक कोच अटेंडेंट अजय मूल रूप से इंदौर का रहने वाला है। वह करीब चार साल से ट्रेन में बतौर अटेंडेंट काम कर रहा है। यह नौकरी उसे निजी एजेंसी के जरिए मिली थी, जिसके पास वेस्टर्न रेलवे के इस रेक के मेंटेनेंस और स्टाफ सप्लाई का ठेका है। आरोपी बीच में कुछ समय के लिए काम छोड़ चुका था। बाद में दोबारा इसी ट्रेन में ड्यूटी पर लौट आया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे लखनऊ में एक व्यक्ति ने दो बैग सौंपे थे।

निजी केबिन और बेडरोल स्टोरेज की सुविधा, यहीं छिपाया

आरोपी अजय फर्स्ट एसी कोच का अटेंडेंट था। कोच में उसके पास निजी केबिन और बेडरोल स्टोरेज की सुविधा थी। दोनों बैग उसी सामान के बीच रखे गए थे। आरपीएफ के मुताबिक उस दिन कैजुअल लेबर और स्टाफ की रूटीन चेकिंग चल रही थी। बातचीत के दौरान आरोपी की हरकतें संदिग्ध लगीं, जिसके बाद बैग खुलवाए गए और कछुओं की तस्करी का खुलासा हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस रूट पर आमतौर पर शराब जैसी अवैध वस्तुओं की जांच होती है, कछुओं की तस्करी की किसी को उम्मीद नहीं थी।

एक कछुआ 2-5 हजार तक, पूरी खेप की कीमत लाखों में

इक्केरियम कारोबार से जुड़े लोगों ने बताया कि छोटे कछुओं की कीमत बाजार में करीब दो हजार से पांच हजार रुपए तक होती है। ये कछुए एक्केरियम शौक के नाम पर खरीदे जाते हैं। जैसे-जैसे इनका आकार बढ़ता है, कीमत भी बढ़ जाती है। इस हिसाब से 311 कछुओं की यह खेप अवैध बाजार में लाखों रुपए की हो सकती थी। हालांकि, वन विभाग का कहना है कि संरक्षित वन्य जीव होने के कारण इनकी कोई कानूनी कीमत तय नहीं की जा सकती।

आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने, राज्य औषधीय पादप बोर्ड के औषधीय पादप डेस्क कैलेंडर-2026 एवं मध्य हर्बल दर्पण मासिक पत्रिका का विमोचन किया।

पेंच टाइगर रिजर्व में 4 शावकों संग दिखी जुगनी बाघिन

पर्यटकों ने जंगल सफारी के दौरान दिखा दुर्लभ नजारा

सिवनी (नप्र)। सिवनी के प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को एक दुर्लभ नजारा देखने मिला। यहां जुगनी बाघिन अपने चार शावकों के साथ बेखौफ अंदाज में चहलकदमी करती नजर आई, जिसका वीडियो सामने आया है।

सफारी पर निकले पर्यटकों की जिप्सी जैसे ही एक वन मार्ग से गुजर रही थी, जुगनी बाघिन और 4 शावक कच्ची सड़क पार करते हुए जंगल की ओर बढ़ते दिखे। इस रोमांचक नजारे को देखकर पर्यटकों में खासा उत्साह देखा गया।

पेंच नेशनल पार्क में पर्यटकों ने देखे बाघों के झलक- देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पेंच नेशनल पार्क में मुख्य रूप से बाघों के दीदार के लिए पहुंचते हैं। इस दुर्लभ दृश्य ने पर्यटकों के सफारी अनुभव को और भी यादगार बना दिया।

पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है, जबकि इसका एक हिस्सा महाराष्ट्र के नागपुर जिले तक विस्तृत है। पेंच नदी के नाम पर बने इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, जिसे बाद में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। शावक जंगल में चहलकदमी करते नजर आए, पर्यटकों ने बनाया वीडियो।

यह अभयारण्य घने जंगलों, हरे-भरे घास के मैदानों और पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। पेंच टाइगर रिजर्व को विश्व प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग की कृति द जंगल बुक से प्रेरित जंगल भी माना जाता है। यहां बाघ और तेंदुए के अलावा भालू, जंगली कुत्ता, चीतल, सांभर, नीलगाय, गौर जैसे अनेक वन्यजीव पाए जाते हैं।

गोविंदपुरा में युवक ने ससुराल में फांसी लगाई, मौत

पत्नी लखनऊ में थी तब उठाया कदम, ससुर ने गेट तुड़वाकर निकाला शव

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में एक फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट नहीं मिलने से खुदकुशी के कारण का खुलासा नहीं हो सका है। घटना मंगलवार रात की है जबकि बुधवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

36 वर्षीय मनोज बहेलिया पुत्र अरुण बहेलिया भोपाल के गोविंदपुरा में सास-ससुर और पत्नी के साथ रहते थे। मनोज मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी के चलते बीते एक साल से ससुर के मकान में रह रहे थे। बीती रात करीब 10 बजे सास खाने के लिए दामाद को बुलाने पहुंची। कमरा अंदर से लॉक था, कई आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो ससुर को बताया गया। सुसाइड नोट नहीं मिलने से खुदकुशी के कारण का खुलासा नहीं हो सका है।

सुसाइड नोट नहीं मिला

ससुर ने पड़ोसियों के साथ मिलकर दरवाजे को तोड़कर शव को फंदे से उतारा। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को कब्जे में लिया और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हो सका है। इन दिनों मनोज की पत्नी लखनऊ स्थित ससुराल में है। पुलिस को सास-ससुर से बातचीत में मनोज द्वारा आर्थिक तंगी से जूझने की जानकारी मिली है। पुलिस सभी एंगल पर मामले की जांच कर रही है।

संपादकीय

राहुल को बोलने देना था...

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिस ढंग से अपनी बात कहने से रोका गया, वह लोकतांत्रिक तरीका नहीं कहा जा सकता। राहुल अगर गलत भी कह रहे थे या संसद के नियम कायदों को उल्लंघन कर रहे थे तो भी उन्हें अपनी बात रखने देनी चाहिए थी। सरकार इस पर अपना जवाब देती और राहुल के आरोपों अथवा शंकाओं को धुर्रे बिखेर सकती थी। लेकिन सरकार ने पहला रास्ता चुनाव। संसद में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी सांसदों ने अध्यक्ष के आसन की तरफ कागज के टुकड़े उछाले। जिसके बाद आसंदी ने 8 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया। लगातार दूसरे दिन भी चले हंगामे के बीच राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में अपनी बात रखने नहीं दी जा रही है और स्पीकर सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। जबकि स्पीकर का कहना था कि राहुल अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं। वो अपनी बात राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखें। फिर भी राहुल नहीं मानें तो सभापति ने सदन की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए दूसरे सांसदों को बोलने के लिए पुकारा। यह सही है कि राहुल भारत चीन तनाव के जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को बेनकाब करना चाह रहे थे, वो 6 साल पुरानी घटना है। वर्तमान संदर्भों में इसका महत्व केवल सैद्धांतिक ही था। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेखित राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में राहुल ने लोकसभा में एक अंग्रेजी पत्रिका 'कारवां' में छपे लेख को कोट करते भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश पढ़े। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि राहुल जिस किताब के अंश कोट कर रहे हैं, वह अभी प्रकाशित ही नहीं हुई है। जहां तक पत्रिका की बात है तो वह कुछ भी लिख सकती है। राहुल ने कहा कि पत्रिका सौ फीसदी प्रामाणिक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस किताब को प्रकाशित नहीं होने दे रही है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में हुए सैन्य तनाव के दौरान मोदी सरकार की अकर्मण्यता की पोल खुल जाती। क्योंकि जब सामने से चीनी टैंक आ रहे थे और सेना प्रमुख शीर्ष नेतृत्व से मार्गदर्शन मांग रहे थे कि हमे क्या करना है, जवाब देना है या नहीं, तब ऐसे निर्णायक क्षण में सरकार तत्काल फैसले ही नहीं ले पा रही थी। जहां तक किसी पत्र पत्रिका में लिखी बात को कोट करने की है तो पूर्व में भी विपक्ष संसद में इसे अपनी बात की पुष्टि के लिए कोट करता रहा है। इसमें नया क्या है? हालांकि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, '349 (1) के तहत ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसका सभा की कार्यवाही से कोई संबंध न हो। इसी कांग्रेस सरकार ने सैटेनिक वर्सेस को बैन कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संविधान और स्पीकर पर भी भरोसा नहीं है। उधर विपक्षी सदस्यों ने राहुल गांधी की बात का समर्थन किया। अगर राहुल गांधी गलत कह रहे थे तो सरकार को उनके आरोपों का पूरी ताकत से खंडन करना चाहिए था। मोदी सरकार चीन के आगे झुकी या नहीं झुकी, यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है। राहुल गांधी के इस आरोप की लद्दाख में चीनी सेना ने भारत का बड़ा भूभाग हथिया लिया है, उसका सच क्या है, यह कभी सामने नहीं लाया गया। अगर चीन ने हमारी और जमीन नहीं हथियाई है तो सरकार सांसदों के सर्वदलीय दल अथवा मीडिया को वहां लेकर इसकी पुष्टि करा सकती थी। आवाज दबाने से तो संदेह गहराता है।

कठिन राजनीतिक परीक्षा है मणिपुर में नई सरकार

नजरिया

अजय कुमार

लेखक लखनऊ निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

करीब एक साल तक राष्ट्रपति शासन में रहने के बाद मणिपुर में फिर से चुनी हुई सरकार बनने जा रही है और इस बार सत्ता की कमान युमनाम खेमचंद सिंह के हाथों में होगी. यह बदलाव सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि उस राज्य के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जो मई 2023 से जातीय हिंसा, विस्थापन और अविश्वास के दौर से गुजर रहा है. मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुआ संघर्ष धीरे-धीरे इतना गहरा हो गया कि पूरा राज्य घाटी और पहाड़ के दो हिस्सों में बंटता दिखने लगा. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस हिंसा में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, 60 हजार से अधिक लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और करीब 350 गांवों में सामान्य जीवन ठप हो गया. हजारों घर, स्कूल, चर्च और मंदिर जला दिए गए, जिससे सामाजिक ढांचा ही नहीं, आर्थिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हुईं.

हिंसा के चलते राज्य का प्रशासन लगभग पंगु हो गया था. राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवागमन बाधित हुआ, कई महीनों तक इंटरनेट बंद रहा और व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ गईं. अनुमान है कि इस संकट से मणिपुर की अर्थव्यवस्था को करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. पर्यटन उद्योग पूरी तरह रुक गया और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा. स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं, क्योंकि कई जिलों में डॉक्टरों और दवाइयों की आपूर्ति बाधित रही. शिक्षा का हाल यह रहा कि हजारों बच्चों की पढ़ाई महीनों तक बंद रही और कई स्कूल राहत शिविरों में बदल दिए गए.

इसी हालात में तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर कुकी समुदाय ने पक्षपात का आरोप लगाया. धीरे-धीरे बीजेपी के भीतर भी असंतोष बढ़ा. अक्टूबर 2024 में पार्टी के करीब डेढ़ दर्जन विधायकों ने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री बदलने की मांग की. दबाव इतना बढ़ा कि फरवरी 2025 में बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया. संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति शासन एक साल से ज्यादा नहीं चल सकता, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर यह मजबूरी बन गई कि नई सरकार का गठन किया जाए. इसी राजनीतिक और संवैधानिक दबाव के बीच युमनाम खेमचंद सिंह का नाम सामने आया.

खेमचंद सिंह का चयन केवल पार्टी के भीतर संतुलन साधने का फैसला नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर लिया गया कदम माना जा रहा है. वे मैतेई समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी मणिपुर में करीब 53 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें कुकी और नागा समुदायों के बीच भी स्वीकार्यता वाला नेता माना जाता है. हिंसा के दौरान वे उन गिने-चुने मैतेई नेताओं में थे, जिन्होंने कुकी राहत शिविरों का दौरा किया और विस्थापित परिवारों से मुलाकात की. नागा बहुल उखरुल जिले में कुकी गांव के राहत शिविर में उनकी मौजूदगी को मानवीय संदेश के तौर पर देखा गया. उस समय जब घाटी और पहाड़ के बीच भरोसे की दीवार सबसे ऊंची थी, खेमचंद की यह पहल एक अलग संकेत थी कि वे केवल अपनी जाति की राजनीति नहीं करना चाहते.

राजनीतिक अनुभव के लिहाज से भी खेमचंद सिंह को मजबूत दावेदार माना गया. वे 2017 और 2022 में सिंगजामेई सीट से विधायक चुने गए. 2017 में पहली बार सत्ता में आने पर उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने पूरे पांच साल सदन की कार्यवाही संभाली. 2022 में वे मंत्री बने और ग्रामीण विकास, पंचायती राज, नगर प्रशासन, आवास और शिक्षा जैसे अहम विभागों की जिम्मेदारी निभाई. मणिपुर की राजनीति में करीब दो दशक से सक्रिय रहने वाले खेमचंद को संगठन और प्रशासन दोनों की समझ रखने वाला नेता माना जाता है. पार्टी नेतृत्व को लगा कि संकट के दौर में एक ऐसा चेहरा जरूरी है, जो अनुभव के साथ-साथ अपेक्षाकृत विवाद रहित भी हो.

मणिपुर विधानसभा का अंकगणित भी इस फैसले को मजबूती देता है. 60 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के पास फिलहाल 37 विधायक हैं. 2022 के चुनाव में पार्टी को 32 सीटें मिली थीं, लेकिन बाद में जेडीयू के पांच विधायक बीजेपी में शामिल हो गए. एक सीट फिलहाल रिक्त है. इसके अलावा एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और 3 निर्दलीय विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं. इस तरह एनडीए के पास कुल 46 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष 14 पर सिमटा है. संख्या के लिहाज से सरकार मजबूत है, लेकिन मणिपुर की राजनीति में असली चुनौती बहुमत नहीं, सामाजिक भरोसा है.

राज्य में आज भी करीब 50 हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं. प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार अब तक केवल 25 से 30 प्रतिशत विस्थापित परिवार ही स्थायी रूप से अपने घर लौट पाए हैं. घाटी और पहाड़ी इलाकों के बीच आवाजाही पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है. कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती के बिना लोगों का आना-जाना संभव नहीं है. सबसे बड़ी चिंता अवैध हथियारों की है. अनुमान है कि हिंसा के दौरान हजारों हथियार लूटे गए या अवैध रूप से जमा किए गए, जिनमें से अब तक केवल एक हिस्सा ही वापस लिया जा सका है. यह स्थिति शांति बहाली के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा मानी जा रही है.

नई सरकार के सामने प्राथमिक चुनौती पुनर्वास और सुरक्षा की होगी. हजारों परिवार जिनके घर जल गए, उनके लिए स्थायी आवास, मुआवजा और रोजगार की व्यवस्था करना आसान काम नहीं है. केंद्र सरकार ने पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज देने की बात कही है, लेकिन जमीन पर इसका असर तभी दिखेगा, जब प्रशासन निष्पक्ष तरीके से काम करे. स्वास्थ्य और शिक्षा को भी दोबारा पटरी पर लाना होगा. आंकड़ों के मुताबिक हिंसा के कारण 100 से ज्यादा स्कूल और दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र आंशिक या पूरी तरह बंद हो गए थे. इन्हें दोबारा चालू करना सरकार की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

बीजेपी की रणनीति यह भी मानी जा रही है कि मुख्यमंत्री मैतेई समुदाय से होंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री पद पर कुकी और नागा समुदाय से प्रतिनिधित्व देकर संतुलन बनाया जाएगा. यह फार्मूला सियासी तौर पर जरूरी है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और पार्टी का लक्ष्य लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटना है. लेकिन चुनावी गणित से पहले सामाजिक गणित को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है. संवाद की प्रक्रिया शुरू करना, रास्ते खोलना, राहत शिविरों को धीरे-धीरे खाली कराना और प्रशासन पर भरोसा लौटाना सरकार की प्राथमिकता होगी.

खेमचंद सिंह की पृष्ठभूमि उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है. वे पेशे से ताइक्वांडो खिलाड़ी और शिक्षक रहे हैं. 1977 में उन्होंने इस खेल की शुरुआत की और करीब 20 साल तक सक्रिय खिलाड़ी रहे. दक्षिण कोरिया में प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारतीय ताइक्वांडो टीम के कप्तान भी बने. बाद में वे खेल प्रशासक बने और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया में उपाध्यक्ष रहे. असम ताइक्वांडो एसोसिएशन की स्थापना से लेकर मणिपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष तक का सफर उन्हें अनुशासन और संगठन की अहमियत सिखाता है. उनके समर्थक मानते हैं कि खेल से आई यही सोच उन्हें राजनीति में भी संतुलित बनाती है.

खेमचंद सिंह को स्वच्छ छवि वाला नेता माना जाता है. विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री रहते हुए उन पर किसी बड़े भ्रष्टाचार या गंभीर विवाद का आरोप नहीं लगा. हिंसा के दौरान उन्होंने सार्वजनिक रूप से शांति की अपील की और कहा कि यह संघर्ष बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए. यही बातें बीजेपी नेतृत्व को यह भरोसा दिलाती हैं कि वे सख्ती और संवेदना के बीच संतुलन बना सकते हैं. मणिपुर की राजनीति में यह संतुलन सबसे कठिन काम है, क्योंकि यहां मुद्दे केवल विकास या रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि पहचान, जमीन और अस्तित्व से जुड़े हैं.

राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में अपेक्षाकृत शांति जरूर लौटी, लेकिन यह शांति प्रशासनिक नियंत्रण से बनी है, सामाजिक मेल-मिलाप से नहीं. नई सरकार के सामने असली चुनौती यही है कि वह लोगों के बीच भरोसा बहाल करे. अगर राहत शिविरों में रह रहे हजारों परिवार अपने घर लौटते हैं, बाजार फिर से खुलते हैं और बच्चे बिना डर के स्कूल जाते हैं, तभी यह माना जाएगा कि सरकार सफल हो रही है. मणिपुर की जनता अब भाषण नहीं, जमीन पर बदलाव देखना चाहती है.

युमनाम खेमचंद सिंह के लिए मुख्यमंत्री बनना केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक अग्निपरीक्षा है. उन्हें साबित करना होगा कि वे केवल पार्टी के नेता नहीं, पूरे राज्य के नेता हैं. अगर वे घाटी और पहाड़ दोनों को साथ लेकर चल पाए, संवाद की राजनीति को प्राथमिकता दी और प्रशासन को निष्पक्ष बनाया, तो वे मणिपुर को हिंसा के अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं. लेकिन अगर अविश्वास और असुरक्षा की दीवारें जस की तस रहीं, तो यह सरकार भी उसी सवालों के घेरे में आ जाएगी, जिनसे बचने के लिए नेतृत्व बदला गया है. मणिपुर की राजनीति में अब असली लड़ाई सत्ता की नहीं, शांति और भरोसे की है, और इसी मोर्चे पर खेमचंद सिंह की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है!

मुक्त व्यापार समझौता यानी संतुलित लाभ की खोज

भारत-यूरोपीय संघ

अरूण कुमार डनायक

लेखक भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक हैं।

भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप दिया है। यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों और वैश्विक जीडीपी के लगभग 25 प्रतिशत हिस्से को प्रभावित करता है। भारत यूरोप से आयातित वाहनों, मशीनरी, रसायनों, औषधियों, कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क घटाएगा, जबकि ईयू भारतीय वस्त्र, परिधान, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, जवाहरात से श्रम-प्रधान क्षेत्रों को शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करेगा। भारत में इस समझौते को केवल व्यापारिक उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी व्यापार अनिश्चितताओं के बीच ईयू समझौता भारत की अमेरिका-केंद्रित निर्भरता से हटकर रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय भूमिका का दावा करता है–इसे अमेरिका के लिए सूक्ष्म राजनीतिक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ एफटीए पर सहमति जताई है, जिसे अमेरिका-केंद्रित व्यापार निर्भरता से बाहर निकलने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस रणनीतिक आख्यान का आकलन कृषि और ऑटोमोबाइल जैसे संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों पर समझौते के प्रभावों से करने की आवश्यकता है। क्या बाजार खोलने के प्रस्ताव भारत की संरचनात्मक कमजोरियां उजागर करते हैं? क्या यह वास्तविक स्वायत्तता मजबूत करता है या सिर्फ बाहरी दबावों की मजबूरी है?

यह एफटीए किसानों के लिए अवसर तो लाता है, पर कृषि क्षेत्र में तनाव और असंतोष की संभावना भी बढ़ाता है। चाय, कॉफी, मसाले, फल-सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्यों को ईयू बाजार में तरजीही पहुंच मिलने से निर्यात बढ़ सकता है। महिलाओं के लिए ग्रामीण रोजगार से किसानों की आय स्थिर होगी। क्योंकि ईयू की तकनीकी सहायता से पैकेजिंग और खाद्य प्रसंस्करण में सुधार हो सकेगा। परंतु अधोसंरचना की कमजोरियाँ और कठोर पर्यावरणीय मानक चुनौती हैं। ये छोटे किसानों के लिए लागत व प्रमाणन का बोझ बन जाते हैं। जिससे निर्यात के संभावित लाभ बड़े निर्यातकों तक सिमटने का जोखिम पैदा होगा।

यह समझौता कृषि को सामूहिक आजीविका के सामाजिक ढाँचे से अलग कर पूंजीवादी कॉरपोरेट समूहों के पक्ष में झुकाता है। गांधी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह कृषि को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अधीन करता है, जहाँ जोखिम किसान उठाता है और लाभ बाज़ारों को मिलता है। इसलिए वैश्विक एकीकरण के साथ-साथ सरकार को एफपीओ सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण और घरेलू विपणन सुधारों पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग पर इस समझौते का प्रभाव तात्कालिक रूप से शेयर बाज़ार में नकारात्मक रहा है। यूरोपीय उन्नत वाहनों पर आयात शुल्क में प्रस्तावित कटौती ने घरेलू निर्माताओं की दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को लेकर आशंकाएँ बढ़ा दी हैं। यद्यपि भारतीय ऑटो उद्योग का बड़ा हिस्सा आम जन के बाज़ार और स्थानीय विनिर्माण पर आधारित है, फिर भी तकनीक, पूँजी और अनुसंधान में मौजूद असमानता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में यह समझौता उद्योग को सुदृढ़ करने के बजाय उसे संरचनात्मक दबाव और संभावित क्षरण की ओर ले जाता है। वस्त्रोद्योग को ईयू बाजार पहुंच और नए रोजगार अवसर मिलेंगे, लेकिन पर्यावरणीय, श्रम व आपूर्ति-श्रृंखला मानकों की बाध्यताओं से लाभ ज्यादातर बड़े निर्यातकों तक सिमट सकता है। दूसरी ओर, मशीनरी और उच्च तकनीक उपकरणों में यह समझौता भारत को आयात-आधारित उपभोक्ता की भूमिका में स्थिर करता है, जिससे स्वदेशी उद्योग, लघु विनिर्माण इकाइयों और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा बाधित होती है।

इस समझौते की एक प्रमुख सीमा भारत के स्टील निर्यात से जुड़ी है। जहाँ भारत वर्तमान में ईयू को लगभग 30 लाख टन स्टील निर्यात करता है, वहीं शुल्क-मुक्त कोटा केवल 16 लाख टन तक सीमित रखा गया है। साथ ही, ऊर्जा-गहन उत्पादों पर यूरोपीय संघ के कार्बन कर से भारत को कोई छूट नहीं मिली है, जिससे शेष निर्यात पर अतिरिक्त लागत का दबाव बना रहेगा। यह समझौता ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका ने भारत पर दंडात्मक शुल्क लगाए हैं और वैश्विक व्यापार व्यवस्था गहरी अनिश्चितता से घिरी हुई है। यद्यपि इसे अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, किंतु भारत पहले ही व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों के स्तर पर अमेरिका से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिससे उसकी वास्तविक सौदेबाज़ी क्षमता सीमित हो जाती है। वस्तुतः आज भी भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जिसमें आर्थिक आकार और सैन्य क्षमता के बावजूद तकनीकी-शोध निपुणता, कुशल कार्यबल युक्त मानव संसाधन, वैश्विक नवाचार नेतृत्व और निर्णायक कूटनीतिक प्रभाव की सीमाएँ बनी हुई हैं। अनेक कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने में असफल रहा है। उसकी सबसे बड़ी नैतिक पूँजी–औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए देशों का समर्थन–अब लगभग इतिहास बन चुकी है। इसी कारण वह आज भी वैश्विक शक्ति-संतुलन में स्वतंत्र धुरी बनने की बजाय अमेरिका जैसे प्रभावशाली केंद्रों पर आंशिक रूप से निर्भर रहने को विवश है। मौजूदा गतिरोध दूर करने की दिशा में विदेश मंत्री जयशंकर का प्रस्तावित अमेरिकी दौरा कुछ सकारात्मक परिणाम दे सकता है। कुछ विश्लेषक एफटीए को विवशता का दस्तावेज़ मानते हैं, जो कृषि जोखिम और आयात निर्भरता उजागर करता है। अन्य इसे रणनीतिक सफलता कहते हैं, जो व्यापार विविधीकरण, रोजगार सृजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से स्वायत्तता मजबूत करती है। हर समझौता अवसर-चुनौतियां लाता है, जिसके लिए सरकार और उद्योग को सुधारों व जोखिम उठाने की जरूरत है। आज कृषि सुधार और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को समान रूप से प्राथमिकता देना आवश्यक है।

यद्यपि अमेरिका ने भारत- ईयू समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है, तथापि वह टैरिफ बढ़ाने जैसे उकसावे वाले कदम शायद ही उठाएगा। भारत के पास अमेरिका के साथ व्यापार समझौता करने और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के अतिरिक्त कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं है। पारंपरिक साझेदार रूस आज यूक्रेन युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों में उलझा है, जबकि चीन–एक उभरती वैश्विक शक्ति होने के बावजूद–भारत के लिए रणनीतिक रूप से अविश्वसनीय पड़ोसी बना हुआ है। यूरोप और मध्य-पूर्व अपने संरचनात्मक संकटों के कारण भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों, विशेषकर भारत के पक्ष में झुके व्यापार अधिशेष, का प्रभावी विकल्प नहीं बन सकते। ऐसे में भारत को वैकल्पिक साझेदारियों के प्रतीकात्मक संकेतों के बजाय अमेरिका के साथ शीर्ष राजनीतिक और कूटनीतिक नेतृत्व स्तर पर प्रत्यक्ष और यथार्थवादी व्यापार वार्ताओं से मौजूदा गतिरोध शीघ्र दूर करना चाहिए, क्योंकि रणनीतिक स्वायत्तता समझौतों की संख्या नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक और कूटनीतिक क्षमता से बनती है। जिसके लिए घरेलू सुधार, तकनीकी निवेश, संस्थागत विश्वसनीयता और कठोर निर्णय लेने का राजनीतिक साहस अनिवार्य शर्तें हैं।

बजट में 'लाड़ले लेखक योजना' का प्रस्ताव

कटाक्ष

राकेश सोहम्

लेखक व्यंग्यकार हैं।

खबर है कि बजट के पूरे प्रस्तुतिकरण भाषण में किसी भी कवि और कविता का उल्लेख नहीं हुआ। इससे साहित्य सेवियों का खोखला भ्रम और गहरा गया है कि वे समाज सुधारक हैं और एक न एक दिन इसका इनाम उन्हें अवश्य मिलेगा। अस्तु, एक साहित्य सेवी ने खुद ही अपना साहित्यिक बजट तैयार कर लिया है। सरकारें अपना बजट रखती हैं सो इसमें बुराई क्या है। ये साहित्यसेवी स्वयं साहित्य की सम्मानीय 'सरकार' हैं। चेले-चपाटी बड़े आदर से उन्हें 'सरकार' का संबोधन देते हैं। हालांकि उनका साहित्यक बजट गोपनीय है। पर उनके निकट साहित्य सेवी ने इस बजट को 'लीक' करने का साहसिक कृत्य कर दिखाया है। उनका निकटस्थ दल-बदलू टाइप का है। वह साहित्य के दीगर मठाधीश को अपनी 'सरकार' मानने लगा है और वर्तमान सरकार की जड़ें खोद रहा है। इसी दलबदलू की जानिब से साहित्यिक-बजट के बहुत ख़ास बिंदु उजागर किए जा रहे हैं।

साहित्यिक जल संरक्षण योजना– जल ही जीवन है। इन दिनों साहित्य में बहुत पानी बह गया है। इसलिए जल संरक्षण के मद्देनजर साहित्य पर केवल 'पानी फेरने' का प्रस्ताव है। इससे पानी भी बचेगा और घर-घर जल पहुंचाने में मदद मिलेगी।

लाड़ले लेखक योजना – लेखकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 'लाड़ली बहना योजना' की तर्ज पर 'लाड़ले लेखक योजना' लाने का प्रस्ताव है। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत कलम घिसने के नाम पर हर महीने लेखकों को 'कलम घिस्सू गुजारा भत्ता' मिला करेगा। इससे वोट बैंक में भी भारी इजाफा होगा।

गरीब साहित्यकार उन्मूलन – अब साहित्य में गरीबों का काम खत्म। मेल के लिए डाटा का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है। प्रकाशन में मानदेय का प्रावधान लगभग समाप्ति पर है। साहित्य में दखल आत्मघाती साबित हो सकता है। साहित्यकार और भी गरीबी की गर्त में जा सकते हैं। इसलिए 'गरीब साहित्य सेवी' को उन्मूलित करने का प्रावधान रखा है। फ्री के छपासी गरीब साहित्यकारों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वे पहले जीविकोपार्जन के अन्य साधनों को जुटाए फिर साहित्य के क्षेत्र में आएं। 'भूखे साहित्य ना होय गोपाला' के महामंत्र को ध्यान में रखते हुए 'गरीब साहित्यकार उन्मूलन' का प्रस्ताव है।

पाठक पर्यावरण संरक्षण-संवर्धन– आजकल प्रकृति-पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की महती आवश्यकता है। जो कवि सोशल मीडिया पर भड़काऊ चित्रों पर कविताएं उकेरकर पाठकों को पर्यावरण की नयी सोच दे रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है।

साहित्यिक बजट में और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं। पर निकटस्थ दल-बदलू साहित्य सेवी बस इतने ही चुरा पाए हैं।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

आभासी स्वर्णिम चमक और चांदी-चांदी

व्यंग्य

सुरेश उपाध्याय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

अरे, सुनती हो,' श्रीमान ने अखबार पढ़ते पढ़ते कुछ ज्यादा ही तेज आवाज में श्रीमतीजी को कहा।

'क्या है ?, सुबह सुबह अखबार में ऐसा क्या मिल गया है ?,' श्रीमतीजी ने किचन से बाहर आकर पूछा।

'अरे, तुम्हारी तो लाटरी लग गई है, किस्मत चमक गई है,' आंखों को चौड़ा करते हुए श्रीमान ने कहा।

'कुछ बताओगे भी या जलेबिया ही बनाते रहोगे,' मुस्कुराते हुए श्रीमतीजी ने कहा।

'अरे, वह सोना जो हमारी शादी के वक्त दो सौ रुपया प्रति तोला (दस ग्राम) था, आज एक लाख सत्तर हजार प्रति तोला और चांदी जो दो हजार रूपए प्रति किलोग्राम थी, आज चार लाख रूपए प्रति किलो के करीब पन्हुच गई है।' इतना सुनकर श्रीमतीजी ने अभी तक गुप्त रखे अपने सोने व चांदी के गहनो का विवरण देते हुए पूछा 'यह सब कितने का हो गया है।' श्रीमान ने गणना करके जैसे ही राशि बताई श्रीमतीजी की तो जैसे चांदी चांदी हो गई और चेहरे पर स्वर्णिम आभा निखर आई। इस खुशी में कुछ मीठा हो जाए की तर्ज पर श्रीमान को फीकी के स्थान पर अतिरिक्त चीनी वाली चाय पीलाकर उन्होने आभासी खुशी का वास्तविक इजहार कर दिया।

हमारा घर भी तो पांच लाख में तैय्यार हो गया था और देखते - देखते आज दो करोड का हो गया है, चाय पीते पीते दोनों ने अपनी आस्तियों (असेट्स) व देयताओं (लायिबिलिटि) का आंकलन कर हैसियत का मूल्यांकन किया। लखपति से करोड़पति की श्रेणी में अंतरण का अहसास उन्हे अपने आप पर गर्व करने का अवसर प्रदान कर रहा था।

कोई भी तेजी सदैव तो नही रह सकती, अवरोध आते हैं और चांदी व सोने के भाव में भी आए। एक हफ्ते में ही सोने में तीस हजार रुपए प्रति तोला व चांदी में एक लाख बीस हजार रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट ने दोनों को चिंता में डाल दिया और अपनी हैसियत का पुनर्मूल्यांकन करने में उनकी चाय का स्वाद कुछ फीका हो गया था।

गिरावट से हुए आंकलन की निराशा को भांपते हुए तथा स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में श्रीमान ने कहा 'यह तो नोशनल लास (आभासी) है, वास्तविक नही क्योंकि हमने अपना सोना व चांदी बेचा नही है।' 'एक्चुअल हो या नोशनल, लोस तो लोस है, काश! हम बेच देते तो वास्तविक लाभ होता की नही।' निराशा के अंदेशे ने श्रीमान को चौकन्ना किया और उन्होने स्थिति से निपटने के लिए गिरावट के दौर में मुनाफे की अपनी सैद्धांतिकी प्रस्तुत की। 'देखो, बिट्टू की शादी के लिए हमें सोने व चांदी के जेवरात खरीदने थे जो उस दौर में हमने नहीं खरीदे हैं। अब बाजार चलते हैं और खरीद लेते हैं। तीस हजार प्रति तोला सोने व एक लाख बीस हजार प्रतिकिलो चांदी पर जो बचत होगी, वह ही हमारा मुनाफा होगा। और हाँ, यह आभासी नही वास्तविक होगा।' वास्तविक मुनाफे की गणित ने आभासी नुकसान की क्षतिपूर्ति कर दी थी। सोने का आभासी निखार वास्तविक हो चुका था और दोनो की एका बार फिर चांदी चांदी हो गई थी। लंच के बाद सराफा जाए या शहर के अन्य हिस्सो के किस बडे शोरूम में जाए, इस पर चर्चा शुरु हो गई थी। कितना सोना व कितना चांदी खरीदना है और आज के भाव के हिसाब से कितने रूपयो की व्यवस्था करनी होगी, श्रीमान ने हिसाब लगाकर श्रीमती को बताया। 'यह व्यवस्था कैसे होगी?,' श्रीमती ने पूछा। शहर में कई व्यापारी गोल्ड पर उधार देते हैं, बैंक भी लोन देते हैं और कई गोल्ड लोन कम्पनियों की शाखाएं भी है। बढ़ी हुई कीमत पर अच्छा लोन मिल जाएगा और हमारा सोना बिकने से भी बच जाएगा। इसी बीच पडोसन आई और अपने गोल्ड लोन की जानकारी देते हुए सलाह मांगी। श्रीमान ने कहा 'इस लोन को चुका दो और सोने के नए भाव से नया लोन ले लो, तुम्हे उसी रकम पर अतिरिक्त धन मिल जाएगा, वह कहते हैं न 'हींग लगे न फिटकरी रंग चौखा आए।'

भावों में स्थिरता अभी आई नहीं थी और उतार चढ़ाव ने उन्हे अपने हैसियत के आंकलन व पूनर्मूल्यांकन का एक नया कार्य सौंप दिया था। इससे उनका साथ में समय और समन्वय बढ़ गया है और दोपहर आसानी से बीतने लगी है।

दृष्टिकोण

डॉ. अनीश कुमार

लेखक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के हिन्दी विभाग में अध्यापन करते हैं ।

पढ़ने और तर्क करने वाला समाज सचमुच आगे बढ़ता है

साहित्य विशेष रूप से सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी, उपन्यास, कविता और नाटक के माध्यम से लेखक समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षाओं को स्वर देते हैं। प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ 'रेणु', महाश्वेता देवी जैसे रचनाकारों की कृतियाँ केवल साहित्य नहीं हैं, बल्कि सामाजिक चेतना के दस्तावेज हैं। इन्हें पढ़कर पाठक केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी महसूस करता है। पुस्तकें लोकतांत्रिक चेतना को भी मजबूत करती हैं। वास्तव में पढ़ा-लिखा समाज ही सवाल पूछ सकता है, तर्क कर सकता है और सत्ता को जवाबदेह बना सकता है। जब नागरिक पढ़ने की आदत विकसित करते हैं, तब वे अफवाह, अंधविश्वास और संकीर्णता से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में सहायक होती है।

पुस्तकें विचारों व भावनाओं का एक मुकम्मल दस्तावेज़ होती हैं। पुस्तकें केवल मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्य के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास की आधारशिला हैं। पढ़ने की प्रक्रिया व्यक्ति को सीमित अनुभवों की दुनिया से निकालकर व्यापक सामाजिक यथार्थ से जोड़ती है। जब मनुष्य पुस्तकों के माध्यम से विभिन्न विचारों, संस्कृतियों, संघर्षों और संभावनाओं से परिचित होता है, तब उसका दृष्टिकोण अधिक परिपक्व और संवेदनशील बनता है। यही संवेदनशीलता सामाजिक बदलाव की पहली शर्त है। पुस्तकें हमें प्रश्न करना सिखाती हैं। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अन्याय, असमानता और शोषण को समझने के लिए आलोचनात्मक दृष्टि आवश्यक होती है, और यह दृष्टि पढ़ने से विकसित होती है। इतिहास, समाजशास्त्र, साहित्य और दर्शन की पुस्तकें यह स्पष्ट करती हैं कि समाज स्थिर नहीं होता, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील होता है। जब पाठक यह जानता है कि अतीत में किन विचारों और आंदोलनों ने समाज को बदला, तो वह वर्तमान की समस्याओं को भी नए सिरे से समझने लगता है।

साहित्य विशेष रूप से सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी, उपन्यास, कविता और नाटक के माध्यम से लेखक समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की पीड़ा, संघर्ष और आकांक्षाओं को स्वर देते हैं। प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ 'रेणु', महाश्वेता देवी जैसे रचनाकारों की कृतियाँ केवल साहित्य नहीं हैं, बल्कि सामाजिक चेतना के दस्तावेज हैं। इन्हें पढ़कर पाठक केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व भी महसूस करता है। पुस्तकें लोकतांत्रिक चेतना को भी मजबूत करती हैं। वास्तव में पढ़ा-लिखा समाज ही सवाल पूछ सकता है, तर्क कर सकता है और सत्ता को जवाबदेह बना सकता है। जब नागरिक पढ़ने की आदत विकसित करते हैं, तब वे अफवाह, अंधविश्वास और संकीर्णता से ऊपर उठकर विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह प्रक्रिया समाज को अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी बनाने में सहायक होती है।

पुस्तकें पढ़ना और तर्कवादी होकर वैज्ञानिक ढंग से बात करना–ये दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं और आधुनिक, प्रगतिशील समाज की बुनियाद बनाती हैं। जहाँ पुस्तकें मनुष्य के विचार-जगत को विस्तृत करती हैं, वहीं तर्कवाद और वैज्ञानिक दृष्टि उन विचारों को विवेक, प्रमाण और तर्क की कसौटी पर कसने का साहस देती है। सामाजिक बदलाव की जो भूमिका पुस्तकों की है, वही भूमिका तर्कवादी चेतना की भी है–दोनों मिलकर अंधविश्वास, रूढ़ि और अवैज्ञानिक सोच को चुनौती देते हैं।पुस्तकें हमें केवल सूचनाएँ नहीं देतीं, बल्कि सोचने की पद्धति सिखाती हैं। इतिहास, दर्शन, विज्ञान और साहित्य की पुस्तकों के माध्यम से पाठक यह समझ पाता है कि हर विचार प्रश्नों, प्रयोगों और बहसों से विकसित हुआ है। जब व्यक्ति पढ़ता है, तो वह यह सीखता है कि किसी भी बात को आँख मूँदकर स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। यही पढ़ने की आदत धीरे-धीरे तर्कवादी दृष्टि को जन्म देती है, जहाँ 'क्यों' और 'कैसे' जैसे प्रश्न केंद्रीय हो जाते हैं।

तर्कवाद का अर्थ केवल विरोध करना नहीं, बल्कि प्रमाण, अनुभव और विवेक के आधार पर बात करना है। वैज्ञानिक सोच यह मानती है कि सत्य स्थिर नहीं होता, बल्कि नए तथ्यों और खोजों के साथ विकसित होता है। पुस्तकें इस सोच को मजबूत करती हैं, क्योंकि वे हमें वैज्ञानिक खोजों, सामाजिक आंदोलनों और वैचारिक संघर्षों का इतिहास बताती हैं। डॉ. आंबेडकर, नेहरू, भगत सिंह जैसे विचारकों की रचनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि पढ़ना और तर्क करना सामाजिक अन्याय के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार रहे हैं। भारतीय समाज के संदर्भ में पुस्तकें और वैज्ञानिक दृष्टि विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ लंबे समय तक अंधविश्वास, जाति-आधारित भेदभाव और रूढ़ परंपराएँ हावी रही हैं। जब व्यक्ति पढ़ता है और तर्क के आधार पर बात करना सीखता है, तब वह किसी चमत्कार, अफवाह या धार्मिक भय के बजाय कारण और परिणाम को समझने की कोशिश करता है। यही सोच समाज को अधिक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण और मानवीय बनाती है।

वहीं दूसरी ओर स्त्रियों,वंचित समुदाय के लिए पुस्तकें केवल ज्ञान का साधन नहीं, बल्कि मुक्ति, आत्मसम्मान और सामाजिक परिवर्तन का औज़ार हैं। जिस समाज में संसाधन, सत्ता और अवसर कुछ वर्गों तक सीमित रहे हों, वहाँ पुस्तकों का महत्व और भी बढ़ जाता है। पढ़ना वंचित व्यक्ति को न सिर्फ़ जानकारी देता है, बल्कि उसे अपनी स्थिति को समझने, प्रश्न करने और बदलने की शक्ति भी देता है। वंचित समुदाय अक्सर इतिहास और मुख्यधारा के विमर्श से बाहर रखे गए हैं। पुस्तकें उन्हें अपना इतिहास जानने का अवसर देती हैं–यह समझने का कि उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका प्रतिरोध कैसे किया गया। डॉ. आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई, तारा शिंदे,पेरियार, बिरसा मुंडा जैसे विचारकों की रचनाएँ वंचित समुदायों के लिए आत्मबोध की किताबें हैं। ये पुस्तकें यह विश्वास पैदा करती हैं कि गरीबी, जाति या हाशिए की पहचान किसी व्यक्ति की क्षमता का पैमाना नहीं है।

पुस्तकें चेतना का निर्माण करती हैं। जब कोई व्यक्ति पढ़ता है, तो वह अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक संरचना के हिस्से के रूप में देखने लगता है। इससे आत्मग्लानि की जगह सामाजिक समझ और सामूहिक संघर्ष की भावना पैदा होती है। यही चेतना वंचित समुदायों को संगठित होने, अपने अधिकारों की बात करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा और पुस्तकों का संबंध वंचित समुदायों के लिए जीवन बदलने वाला होता है। पुस्तकों के माध्यम से विकसित तर्कवादी और वैज्ञानिक सोच अंधविश्वास, डर और परंपरागत दबावों को तोड़ती है, जिनका उपयोग अक्सर वंचना को बनाए रखने के लिए किया जाता है। पढ़ा-लिखा व्यक्ति सवाल करता है, प्रमाण मांगता है और सत्ता को चुनौती देने का साहस जुटाता है।

आज के डिजिटल युग में भी पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। चाहे कागज़ की किताब हो या ई-पुस्तक, पढ़ने की आदत व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करती है। सामाजिक बदलाव किसी एक दिन में नहीं आता; यह चेतना, विचार और संवाद की लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है, और इस प्रक्रिया की सबसे सशक्त माध्यम पुस्तकें ही हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि पुस्तकें पढ़ना केवल व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक, संवेदनशील और परिवर्तनशील समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य है। पुस्तकें यहाँ संतुलन का काम करती हैं–वे गहराई, संदर्भ और आलोचनात्मक दृष्टि देती हैं। इस प्रकार, पुस्तकें पढ़ना और तर्कवादी होकर वैज्ञानिक बात करना केवल व्यक्तिगत बौद्धिक विकास का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और बदलाव की अनिवार्य शर्त है। एक ऐसा समाज, जो पढ़ता है और तर्क करता है, वही समाज सचमुच आगे बढ़ता है।

मानसिक स्वास्थ्य

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

लेखक वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं।

डिजिटल लत : जनस्वास्थ्य का मुद्दा

डिजिटल लत अब किसी शौक या आदत का नाम नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौती है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारना आवश्यक है। सरकार को तुरंत ऐसी नीति बनानी चाहिए जो ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बच्चों को लक्षित डिजिटल खतरों को नियंत्रित कर सके। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया अनिवार्य हो ताकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए समय सीमा, रात का गेमिंग कर्फ्यू और स्वास्थ्य चेतावनियाँ लागू की जा सकें।

गाजियाबाद की तीन बहनों की आत्महत्या सिर्फ एक परिवार की पीड़ा नहीं, बल्कि भारत में बढ़ते डिजिटल संकट की सबसे भयावह तस्वीर है। यह घटना साफ बताती है कि हाई-डोपामिन ऑनलाइन गेम, अनियंत्रित स्क्रीन टाइम और डिजिटल दुनिया का दबाव आज बच्चों और किशोरों की मानसिकता को गहराई से चोट पहुँचा रहा है। बच्चे मोबाइल के अंदर चलने वाली कृत्रिम उत्तेजनाओं, पुरस्कार आधारित गेमिंग और एल्गोरिथ्म द्वारा नियंत्रित व्यवहार में इतने उलझ जाते हैं कि वास्तविक जीवन, पढ़ाई, परिवार और भावनात्मक संतुलन सब पीछे छूट जाता है। जब माता-पिता सीमाएँ लगाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों में तनाव, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और कई बार अत्यधिक नकारात्मक फैसले सामने आते हैं।

डिजिटल लत अब किसी शौक या आदत का नाम नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौती है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारना आवश्यक है। सरकार को तुरंत ऐसी नीति बनानी चाहिए जो ऑनलाइन गेमिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बच्चों को लक्षित डिजिटल खतरों को नियंत्रित कर सके। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया अनिवार्य हो ताकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए समय सीमा, रात का गेमिंग कर्फ्यू और स्वास्थ्य चेतावनियाँ लागू की जा सकें।

स्कूलों में डिजिटल वेलनेस को अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिससे बच्चे समझ सकें कि स्क्रॉल, रिवार्ड सिस्टम, वर्चुअल इंटरैक्शन और लगातार उत्तेजना उनके दिमाग को कैसे प्रभावित करती है। हर जिले में डिजिटल एडिक्शन क्लिनिक स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और साइबर विशेषज्ञ मिलकर बच्चों और अभिभावकों को सहायता दे सकें।

मोबाइल और टेक कंपनियों को अपने हर डिवाइस में सुरक्षित चाइल्ड मोड शामिल करना चाहिए जिसमें स्क्रीन लिमिट, कंटेंट फिल्टर, पैरेंट नोटिफिकेशन और स्लीप टाइम जैसी सुविधाएँ पहले से मौजूद हों। सरकार को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़े नियम लागू करने होंगे ताकि बच्चों को हानिकारक कंटेंट और डोपामिन आधारित डिज़ाइन से बचाया जा सके।

कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को भी डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण देना जरूरी है ताकि वे साइबर बुलिंग, गेमिंग लत और ऑनलाइन खतरों से जुड़े मामलों को संवेदनशील रूप से समझ सकें।

आत्महत्या जैसे मामलों में डिजिटल बिहेवियर ऑटोप्सी को अनिवार्य किया जाना चाहिए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बच्चा किन ऑनलाइन प्रभावों या दबावों के अधीन था।

भारत को यह स्वीकारना होगा कि डिजिटल लत एक उभरती हुई मनोवैज्ञानिक महामारी है। यह केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन, भावनात्मक संतुलन, पढ़ाई, सामाजिक जुड़ाव और भविष्य पर गहरा असर डालने वाला संकट है। अगर हम इस समय उचित कदम नहीं उठाते, तो ऐसी त्रासदियाँ बढ़ती जाएँगी और समाज इसके लिए तैयार नहीं होगा। हर बच्चे की मानसिक सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे सुरक्षित करना आज सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

चर्चा में वेनेजुएला

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

तेल ही नहीं सबसे ऊंचे जलप्रपात के लिए भी प्रसिद्ध है

राजनीतिक संदर्भों और आग्रहों से अलग हटकर देखें तो जानने को मिलता है कि वेनेजुएला का तेल और रूस या अरब देशों का तेल रासायनिक रूप से एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। इसे समझने के लिए हमें तेल की 'क्वालिटी' और 'निकालने की प्रक्रिया' पर ध्यान देना होगा। वेनेजुएला में मुख्य रूप से 'अति-भारी कच्चा तेल' पाया जाता है। यह कोलतार (tar) जैसा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसे पाइपलाइनों में बहाने के लिए इसमें हल्का तेल या केमिकल मिलाना पड़ता है। जबकि रूस/सऊदी अरब का तेल आमतौर पर 'हल्का' या 'मीडियम' होता है। यह पानी की तरह पतला होता है और इसे आसानी से निकाला और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वेनेजुएला का तेल 'सोर' होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें सल्फर (गंधक) की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसे रिफाइन करना कठिन और महंगा होता है क्योंकि सल्फर निकालने के लिए जटिल तकनीक चाहिए। रूस : रूस का तेल 'मीडियम सोर' होता है। सऊदी अरब का तेल काफी हद तक 'स्वीट' होता है, जिसमें सल्फर कम होता है और इसे रिफाइन करना सबसे आसान होता है।

हाल ही में भारत से बहुप्रतीक्षित अमेरिका से सशर्त ट्रेड डील हो जाने का समाचार आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित रूप से दावा किया है कि भारत रूस की बजाए अब वेनेजुएला से कच्चा तेल लेगा।

वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल तेल भंडार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वर्तमान में (फरवरी 2026), यह देश एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील ऐतिहासिक मोड़ से गुजर रहा है। जनवरी 2026 में, अमेरिकी सैन्य अभियान 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेकर अमेरिका ले जाया गया । वर्तमान में देश एक संक्रमणकालीन दौर में है। डेल्सी रोड्रिगेज ने कुछ समय के लिए जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। देश में लंबे समय से 'बोलिवेरियन क्रांति' (समाजवाद) और विपक्षी ताकतों के बीच संघर्ष रहा है।

राजनीतिक संदर्भों और आग्रहों से अलग हटकर देखें तो जानने को मिलता है कि वेनेजुएला का तेल और रूस या अरब देशों का तेल रासायनिक रूप से एक-दूसरे से काफी अलग होते हैं। इसे समझने के लिए हमें तेल की 'क्वालिटी' और 'निकालने की प्रक्रिया' पर ध्यान देना होगा। वेनेजुएला में मुख्य रूप से 'अति-भारी कच्चा तेल' पाया जाता है। यह कोलतार (tar) जैसा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इसे पाइपलाइनों में बहाने के लिए इसमें हल्का तेल या केमिकल मिलाना पड़ता है। जबकि रूस/सऊदी अरब का तेल आमतौर पर 'हल्का' या 'मीडियम' होता है। यह पानी की तरह पतला होता है और इसे आसानी से निकाला और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। वेनेजुएला का तेल 'सोर' होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें सल्फर (गंधक) की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसे रिफाइन करना कठिन और महंगा होता है क्योंकि सल्फर निकालने के लिए जटिल तकनीक चाहिए। रूस : रूस का तेल 'मीडियम सोर' होता है। सऊदी अरब का तेल काफी हद तक 'स्वीट' होता है, जिसमें सल्फर कम होता है और इसे रिफाइन करना सबसे आसान होता है।

वेनेजुएला के भारी तेल से डीजल या गैसोलीन बनाने के लिए बहुत ही आधुनिक और विशेष 'कॉम्प्लेक्स रिफाइनरीज' की आवश्यकता होती है। दुनिया की बहुत कम रिफाइनरियाँ ही (मुख्यतः अमेरिका और भारत में) इसे कुशलता से प्रोसेस कर सकती हैं। जबकि रूस या अरब देशों के तेल को साधारण रिफाइनरियों में भी आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है।

दरअसल वेनेजुएला का तेल 'मात्रा' में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन 'गुणवत्ता' के मामले में यह रूस और सऊदी अरब के मुकाबले काफी कठिन और महंगा हो जाता है। यही कारण है कि भारी तेल होने के बावजूद वेनेजुएला अपनी अर्थव्यवस्था को उतनी तेजी से नहीं संभाल पाया, क्योंकि इसे बेचने के लिए उसे विदेशी तकनीक और विशेष रिफाइनरियों पर निर्भर रहना पड़ता है।

वेनेजुएला की तेल प्रधान देश होने जैसी विशेषता के अलावा इसका पर्यटनीय महत्व भी कम नहीं है। वेनेजुएला को 'लैंड ऑफ ग्रेस' कहा जाता है। यहाँ एंडीज पर्वत, अमेज़न वर्षावन, विशाल घास के मैदान और कैरेबियन तट रेखा का अनूठा संगम मिलता है। दुनिया का सबसे ऊँचा निर्बाध जलप्रपात 'एंजेल फॉल्स' स्थित है, जिसकी ऊँचाई लगभग 979 मीटर है। लेक मार्काइबो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे पुरानी झीलों में से एक है, जिसके नीचे तेल के विशाल भंडार हैं। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है, लेकिन ऊँचाई के साथ तापमान में बदलाव आता है। यद्यपि फिलहाल कई देशों ने यहां की यात्राओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है तथापि वेनेजुएला के प्राकृतिक दृश्यों और जनजीवन ने पर्यटकों और घुमक्कड़ों को सदैव आकर्षित किया है।

सोहागपुर पुलिस की अपील

स्कूल, ट्यूशन आदि कार्यों के लिए नाबालिगों को वाहन न चलाने दें अभिभावकगण

सुबह सवेरे सोहागपुर। सोहागपुर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अभिभावकगण स्कूल ट्यूशन आदि कार्यों के लिए नाबालिगों को वाहन चलाने न दे। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों सेन्ट पैट्रिक स्कूल के तीन होनहार छात्रों की ट्यूशन से वापिस घर जाते समय बिना रेडियम लगे खड़े ट्रेक्टर ट्राली से टकराने से घटना स्थल पर मौत हो गई थी। इसी तारतम्य में विगत दिवस पुलिस नेविशेष अभियान चलाकर नगर के निजी स्कूलों के सामने नाबालिगों के वाहन स्कूल के बाहर खड़े हुए थे।उनके अभिभावकों को बुलाकर समझाने के साथ मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई की गई। जिसमें पुलिस ने 17 प्रकरण करीबन दस हजार रुपए की राशि समन शुल्क वसूली की गई। ज्ञातव्य है कि उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य चालान तक सीमित नहीं था । बल्कि मुख्य उद्देश्य मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की प्रति नागरिकों एवं अभिभावकों छात्रों को जागरूक करना था। ताकि नाबालिकों छात्र छात्राएं की वाहन चलाने से कोई दुर्घटना घटित न हो पाए। वहीं सोहागपुर पुलिस ने वर्तमान में शादी विवाह प्रारंभ होने के साथ इसी माह के मध्य से बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य परीक्षाएं भी प्रारंभ हो रही हैं ।

जिला उत्कृष्ट व मॉडल स्कूल एवं श्रमोदय आवासीय प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी को

मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी की परीक्षा तिथि, प्रदेशभर में बनाए गए 386 परीक्षा केंद्र

बैतूल। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जिला उत्कृष्ट व मॉडल स्कूल एवं श्रमोदय आवासीय प्रवेश चयन परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा 8 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक चलेगी। श्रमोदय आवासीय प्रवेश परीक्षा में कुल 2 हजार 870 विद्यार्थी एवं जिला उत्कृष्ट/मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा में 80 हजार 699 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए प्रदेशभर में कुल 386 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड बैतूल के प्रभारी राजेश करोले ने बताया कि बैतूल शहर में 12 परीक्षा केंद्र और 6 विकास खंड में उत्कर्ष चयन परीक्षा एवं मॉडल चयन परीक्षा के साथ-साथ श्रमोदय की भी परीक्षा का केंद्र बैतूल ई.एफ.ए. शासकीय कन्या उमावि बैतूल गंज है। मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि सभी परीक्षार्थी समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें तथा निर्धारित तिथि एवं समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों।

14 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

बैतूल। गंज थाना क्षेत्र के कुम्हार टेक गांव में मंगलवार रात 14 वर्षीय नाबालिग बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन जब घर लौटे तो उन्होंने बालिका को घर के अंदरूनी कमरे में दुपट्टे से झूलता पाया। पुलिस को घटना की सूचना रात करीब 9.30 बजे मिली। परिजनों ने उसे तुरंत नीचे उतारा और अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने रात करीब 11.30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, बालिका पांचवीं कक्षा तक पढ़ी थी और कुछ समय से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। घटना के समय उसकी मां भट्टे पर काम करने गई थीं, जबकि पिता मवेशी चराने जंगल गए थे। घर लौटने पर पिता ने ही उसे फंदे से नीचे उतारा और पुलिस को सूचना दी। बताया जा रहा है कि बालिका ने घर में ही फांसी लगाई थी। परिजनों ने बताया कि उसने कभी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की थी। गंज पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता चल सके।

मप्र विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन का सम्मेलन आगामी 7 को

बैतूल। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन बैतूल का स्नेह सम्मेलन शनिवार 7 फरवरी को सागौन बाबा दरबार, परशुराम चौक (कॉलेज चौक) के पास बैतूल में आयोजित होगा। एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष डीके तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। इसमें पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णयों व पेंशनर्स की समस्याओं पर चर्चा की जायेगी। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर संयुक्त मोर्चा के विधि सलाहकार एमएम अंसारी, जो एसोसिएशन शाखा सचिव भी है, वह मोर्चा द्वारा निर्धारित प्रदेश के सभी सर्किल/जिलों में विद्युत पेंशनर्स के दो सूत्रीय मांग पत्र पेंशन गारंटी और केंद्र के समान घोषित दर व दिनांक से महंगाई राहत का भुगतान के लिए जारी संघर्ष अनुसार 11 फरवरी को कैंपेन हाउस लिंक रोड परिसर बैतूल में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धरना-प्रदर्शन तथा महाप्रबंधक मध्य क्षेत्र विधुत वितरण कंपनी बैतूल को ज्ञापन दिए जाने की रूपरेखा तथा आगामी संघर्ष कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी सभी को देंगे।

नपा ने ठेकेदार को वर्क आर्डर जारी कर काम शुरू करने के लिए किया निर्देशित

महानगरों की तर्ज पर नजर आयेगी नेहरू पार्क की चौपाटी

एस. द्विवेदी, बैतूल। महानगरों की तरह ही बैतूल शहर की चौपाटी भी जल्द आकर्षक अंदाज में नजर आएगी। इसके कायाकल्प पर नगरपालिका द्वारा 1.62 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे है। इस कार्य के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। ठेकेदार को वर्क ऑर्डर भी दिया जा चुका है और जल्द कार्य शुरू करने के लिए भी कहा है। योजना के तहत चौपाटी में संचालित अस्थायी हाथ ठेलों को हटाकर 100 से अधिक आधुनिक, एक समान डिजाइन की स्थायी दुकानें बनाई जाएंगी, जिससे चौपाटी का लुक पूरी तरह आधुनिक और आकर्षक हो जाएगा। चौपाटी का यह कायाकल्प विधायक हेमंत खंडेलवाल की परिकल्पना और निरंतर प्रयासों से संभव हो पाया है। नगरपालिका के अनुसार नेहरू पार्क चौपाटी में 122 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में यहां अधिकांश दुकानदार हाथ ठेलों और अस्थायी ढांचों में व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे न केवल अव्यवस्था रहती है बल्कि सौंदर्यीकरण भी प्रभावित होता है। नए प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी दुकानों का एक ही आकार और एक ही डिज़ाइन होगा। प्रत्येक दुकान का साइज 10 बाय 10 फीट निर्धारित किया गया है, ताकि सभी दुकानदारों को समान सुविधा मिल सके। इसके अलावा यहां पेवर ब्लॉक, रेलिंग एवं डेकोरेटिव लाइट्स भी लगाई जाएंगी।

विधायक की मंशानुरूप तैयार किया है प्रोजेक्ट

नेहरू पार्क चौपाटी केवल ठेले और अस्थायी दुकानों तक सीमित न रहे, बल्कि यह शहरवासियों के लिए एक सुव्यवस्थित, आकर्षक और आधुनिक फूड स्ट्रीट के रूप में विकसित हो, यहीं बैतूल विधायक की भी मंशा रही है। उनकी इसी सोच को मूर्त रूप देने के लिए नगरपालिका द्वारा यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। योजना के तहत चौपाटी को न सिर्फ व्यवस्थित किया जाएगा, बल्कि इसे शहर की पहचान के रूप में भी विकसित किया जाएगा। हालांकि चौपाटी में व्यवसाय करने वाले दुकानदारों की संख्या सूची से कहीं अधिक बताई जा रही है। ऐसे में सूची से बाहर रह गए दुकानदारों को कहां और कैसे स्थान मिलेगा, इस मुद्दे पर नगरपालिका की ओर से अभी कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है।

बढ़ सकता है दुकानों का किराया

चौपाटी पर एक जैसी बनाई जाएंगी। 122 दुकानें प्रोफाइल शीट की बनाई जाएंगी और सभी दुकानें 10 बाय 10 फीट में बनेगी। इन दुकानों का किराया भी अधिक हो सकता है। बताया जा रहा है कि वर्तमान में चौपाटी पर दुकानें लगाने वाले दुकानदारों से नगरपालिका द्वारा 20 रुपए प्रतिदिन प्रति दुकान के हिसाब से किराया वसूला जाता है। कायाकल्प के बाद सुविधाएं तय है। हालांकि अभी किराये की बढ़ने के साथ किराये में इजाफा होना अंतिम दर तय नहीं की गई है, अनुमान लगाया जा रहा है कि दुकानें बनने के बाद किराया में भी वृद्धि हो सकती है। बताया गया कि करीब एक साल पहले नगरपालिका द्वारा चौपाटी के दुकानदारों का सर्वे कराया था। इसी आधार पर सर्वे के बाद 122 अलग-अलग दुकानदारों की सूची तैयार की गई है। इन्हीं सूचीबद्ध दुकानदारों को नई दुकानें आवंटित की जाएंगी।

बेहद आकर्षक नजर आयेगी चौपाटी

चौपाटी को आकर्षक बनाने के लिए, केवल दुकानें ही नहीं, बल्कि पूरे परिसर का सौंदर्गीकरण किया जाएगा। योजना के तहत चौपाटी में रेलिंग, आधुनिक डेकोरेटिव लाइटिंग और बेहतर ले-आउट तैयार किया जाएगा। शाम के समय चौपाटी रोशनी से जगमगाएगी, जिससे यहां लोगों के लिए एक पसंदीदा पारिवारिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगी। फिलहाल नगरपालिका ने ठेकेदार को वर्कआर्डर कर दिये है और जल्द ही काम शुरू करने के लिए भी कहा है। नपा द्वारा निर्माण कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है, ताकि दुकानदारों और लोगों को कम से कम परेशानी हो।

इनका कहना है -

नेहरू पार्क के पास 1.62 करोड़ रुपए से चौपाटी पर 122 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। इसका वर्क आर्डर भी ठेकेदार को दे दिया है और जल्द काम शुरू करने के लिए कहा है। यहां बनने वाली सभी दुकानों का साइज और डिजाइन एक जैसी होगी। जिससे चौपाटी बेहद आकर्षक नजर आयेगी।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

अग्निवीर भर्ती 2026 में आयु सीमा बदलाव का विरोध

ओवरएज हुए अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

बैतूल। अग्निवीर योजना 2026 की भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में बदलाव के विरोध में बैतूल में युवाओं ने प्रदर्शन किया। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में युवा कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने बताया कि हाल ही में भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा को 1 अक्टूबर 2005 से बदलकर 1 जुलाई 2006 कर दिया गया है। इस बदलाव के कारण हजारों अभ्यर्थी, जो पहले पात्र थे, अब ओवरएज हो

गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई युवा पिछले कई वर्षों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे, जिनमें से कुछ तो गांव छोड़कर बैतूल में रहकर प्रशिक्षण ले रहे थे। इस अचानक हुए बदलाव से उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि अग्निवीर भर्ती 2026 में एक बार के लिए आयु सीमा में विशेष छूट (वन टाइम एज रिलैक्सेशन) दी जाए। उनका तर्क है कि इससे उन युवाओं को अवसर मिल सकेगा, जो पूर्व मानकों के अनुसार तैयारी कर रहे थे। युवाओं ने कहा कि वे वर्षों से अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और राष्ट्र सेवा की भावना के साथ तैयारी कर रहे थे। आयु सीमा अचानक घटा दिए जाने से उनका मनोबल टूट गया है। उन्होंने सरकार से इस मामले में न्यायसंगत और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है।

ग्राम कनौजिया में पहुंचा कृषि रथ, किसानों को मिली आधुनिक खेती की जानकारी

बैतूल। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अवसर पर आमला विकासखंड की ग्राम पंचायत कनौजिया में बुधवार को कृषि रथ के माध्यम से कृषक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों एवं शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उपसंचालक कृषि बैतूल डॉ. आनंद बड़ोनिया ने बताया कि

कार्यशाला के दौरान किसानों को ई-टोकन प्रणाली, नरवाई प्रबंधन के लिए उपयोगी आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे स्ट्रा रीपर, रीपर-कंबाइनर की जानकारी दी गई। इसके साथ ही ई-यंत्र पोर्टल के माध्यम से कृषि यंत्रों पर मिलने वाले अनुदान की प्रक्रिया भी विस्तार से समझाई गई। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के फायदे बताते हुए रासायनिक लागत कम कर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पशुपालन एवं उद्यानिकी विभाग की योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग से डॉ. प्रमोद मीणा, कृषि वैज्ञानिक डॉ. एसके तिवारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सतीश भोंडे, पशुपालन विभाग से हेमलता नागले, शीला नागले, उद्यान विस्तार अधिकारी एवं क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन की चुप्पी से सचिवों में बढ़ी नाराजगी, काम बंद-कलम बंद की तैयारी

बैतूल। चिचोली विकासखंड में पदस्थ पंचायत सचिव के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन द्वारा जिला मुख्यालय पर दिए गए तीन दिवसीय अल्टीमेटम का एक दिन बीत जाने के बाद भी दोषी आरोपी के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से जिलेभर के पंचायत सचिवों में नाराजगी और असंतोष गहराता जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी को लेकर संगठन ने आंदोलन को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। मंगलवार 3 फरवरी को जिला मुख्यालय बैतूल पहुंचकर मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत, नर्मदापुरम के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष देवनाथ बागमरे एवं जिला अध्यक्ष लक्ष्मीचंद अमरुते के नेतृत्व में जिले के दसों विकासखंडों के अध्यक्षों और सैकड़ों पंचायत सचिवों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में दोषी आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई, पंचायत सचिवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, शासकीय सेवकों के सम्मान और संरक्षण के लिए स्पष्ट निर्देश जारी करने सहित जनपद पंचायत स्तर पर साप्ताहिक बैठक के स्थान पर मासिक

बैठक आयोजित करने और प्रत्येक माह 1 से 5 तारीख के बीच वेतन भुगतान की मांग की गई थी। ज्ञापन सौंपते समय संगठन ने स्पष्ट रूप से तीन दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी थी कि यदि निर्धारित समयसीमा में न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई तो पंचायत सचिव काम बंद-कलम बंद हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। अल्टीमेटम का पहला दिन बीत जाने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से संगठन में रोष और बेचैनी का माहौल है। प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत ने पूर्व में स्पष्ट किया था कि पंचायत सचिव शासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं, ऐसे में उन पर हमला निंदनीय है। वहीं जिला अध्यक्ष लक्ष्मीचंद अमरुते और संभाग के कार्यवाहक अध्यक्ष देवनाथ बागमरे ने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस आंदोलन के दौरान जिले के दसों ब्लॉक अध्यक्ष राजेन्द्र गंगारे, विजय मालवी, धनराज बड़ोदे, राजू पंडाग्रे, संतोष लोखंडे, रोशन यादव, राजेन्द्र झरबड़े, नामदेव खाड़े, रामदास बारपेटे, मनोहर बमोरिया सहित बड़ी संख्या में पंचायत सचिव उपस्थित रहे। संगठन ने साफ संकेत दिए हैं कि अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं और अगला कदम निर्णायक होगा।

जिले के 4 केंद्रों पर 518 बच्चों ने लिया स्वर्ण प्राशन का लाभ

बैतूल। आयुष विभाग द्वारा आयोजित स्वर्ण प्राशन कार्यक्रम में जिले के 4 स्थानों पर कुल 518 बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाया गया। यह आयोजन प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र पर किया जाता है। इस बार भी कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें डाबर फार्मास्यूटिकल्स का सहयोग प्राप्त हुआ। आयुष विभाग द्वारा प्रत्येक माह मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में 2 फरवरी को जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर योगेश चौकीकर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉक्टर योगेश चौकीकर द्वारा औषधालय समय पर खुलने, कर्मचारियों को गणवेश में उपस्थित रहने, आगंतुकों से सदाचारपूर्ण व्यवहार कर औषधि प्रदान करने के निर्देश

दिए गए। अन्य विभागीय विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा विभागीय निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने हेतु बैठक के मध्य में योग ब्रेक भी लिया गया। जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर बाल्य रोग विशेषज्ञ ने बताया कि स्वर्ण प्राशन औषधि में स्वर्ण भस्म के साथ शंखपुष्पी, ब्राम्ही, वचा, विषम मात्रा में घृत एवं शहद का मिश्रण होता है। बदलते मौसम में स्वर्ण प्राशन से बच्चों का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है तथा बीमारियों से लडने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसे बच्चों के लिए अमृत तुल्य बताया गया है, जो उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत हितकर है।

अगला पुष्य नक्षत्र 28 फरवरी को

स्वर्ण प्राशन का आयोजन शासकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय टिकारी में 371 लाभार्थी, जिला आयुष विंग बैतूल में 40 लाभार्थी, शासकीय आयुर्वेद औषधालय गर्ग कॉलोनी में 75 लाभार्थी तथा शासकीय आयुर्वेद औषधालय भैंसदेही में 32 लाभार्थी बच्चों के लिए किया गया। इस प्रकार कुल 518 लाभार्थी बच्चों ने स्वर्ण प्राशन का लाभ प्राप्त किया। अगला पुष्य नक्षत्र 28 फरवरी को है। सभी माता-पिता से आग्रह किया गया है कि वे अपने 6 माह से 16 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन हेतु अवश्य लेकर आएं और इसका लाभ प्राप्त करें।

मंडीदीप, सोहागपुर में होगा खिताबी मुकाबला

स्वतंत्रता सेनानी स्व. चौहान स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में 33 साल बाद पहुंची सोहागपुर

सुबह सवेरे सोहागपुर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय ठाकुर प्रताप भानु सिंह चौहान की स्मृति में अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2026 के 61वें वर्ष में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय में पांचवां दिन सोहागपुर के खेलप्रेमियों के लिए ऐतिहासिक बन गया। जिसमें खेले मेजबान टीम सोहागपुर ने शानदार प्रदर्शन करते उज्जैन की टीम को पराजित कर दिया। सोहागपुर लगभग 33 सालों के उपरांत फाइनल मुकाबले में पहुंची है। आज की प्रतियोगिता नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता यशवंत पटेल,नगर निरीक्षक उषा मरावी आदि के आतिथ्य में आयोजित हुई। आज की पहला सेमीफाइनल मंडीदीप एवं इटारसी के मध्य खेला गया। मंडीदीप ने आरंभ से ही संतुलित आक्रमण शैली, मजबूत रक्षापंक्ति तेज पासिंग और सटीक फिनिश का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मंडीदीप ने इटारसी को 3-1 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय में दूसरा सेमीफाइनल मेजबान टीम एवं उज्जैन के बीच

हुआ । दोनों टीमों ने कलात्मक हांकी का प्रदर्शन करते

समय सीमा में मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। निर्णायक के निर्देश पर ट्राई ब्रेकर हुआ। ट्राई ब्रेकर में सोहागपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उज्जैन को 3 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। सोहागपुर टीम ने 33 सालों बाद फाइनल में पहुंचीं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1993 में सोहागपुर टीम ने इंदौर पुलिस को हराकर फाइनल पहुंची थी। आज सोहागपुर मेजबान टीम के फाइनल में प्रवेश करने पर खेलप्रेमियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से टीम का स्वागत किया। आज खेलप्रेमियों से प्रतियोगिता का स्थल खचा-खच भरा हुआ था।

फाइनल हाकी मुकाबला होगा रोमांचक

जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय में फाइनल मुकाबला सोहागपुर बनाम मंडीदीप के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन हाकी का प्रदर्शन किया था। गुरूवार को भी खेलप्रेमियों को कलात्मक हांकी देखने को मिलेगी। ज्ञातव्य है कि जिले के एक मात्र खेल मैदान के ज्वाला सिंह श्रद्धा सिंह शाला परिसर ने की नामी-गिरामी हांकी खिलाड़ी देश प्रदेश महाकौशल क्षेत्र को दिए हैं। वर्तमान में उक्त खेल मैदान में सांदीपनि स्कूल निर्माणाधीन है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले को देखने प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, आयोजन समिति के पदाधिकारी , जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय के पदाधिकारी गणमान्य नागरिक एवं खेलप्रेमियों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। आयोजन समिति ने नागरिकों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय प्रताप भानु सिंह चौहान स्मृति हाकी प्रतियोगिता के फाइनल में उपस्थिति होने की अपील की है।

गोला फेंक में सुनीता प्रथम, प्रियंका दूसरे स्थान पर रही

बैतूल। खेल मंत्रालय भारत सरकार एवं मेरा युवा भारत बैतूल युवा कार्यक्रम द्वारा दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन भीमपुर के मॉडल स्कूल खेल परिसर में आयोजित किया गया। जिसके अंतर्गत प्राचीन खेल कबड्डी, रस्सा कसी, गोला फेक, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जनपद अध्यक्ष भीमपुर भैया लाल इरपाचे, प्राचार्य मॉडल स्कूल भीमपुर श्रीमती आशा साहू के आतिथ्य में और जिला अधिकारी श्रीमती सुषमा गवली की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर सुषमा गवली ने बताया कि भारत सरकार मेरा युवा भारत द्वारा इस तरीके के आयोजन ब्लॉक स्तर पर किए जा रहे हैं। जिससे ग्रामीण अंचल में छिपी हुई प्रतिभा अपनी प्रतिभा निखार सके। जनपद अध्यक्ष श्री इरपाचे ने कहा कि सरकार के द्वारा खेल जगत के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधि जन जागरूकता के कार्यक्रम

संचालित किया जा रहे हैं जिससे प्रतिभाओं को अनेक ऊंचाई तक पहुंचने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। कार्यक्रम में कबड्डी में प्रथम स्थान जूनियर युवा मंडल भीमपुर व उपविजेता बजरंग क्लब बेला रहा, गोला फेक में प्रथम स्थान सुनीता व द्वितीय स्थान प्रियंका धुर्वे, पुरुष वर्ग गोला फेंक में शेशपाल इवने प्रथम, द्वितीय स्थान लोकेश ने, 100 मीटर दौड़ में सुनीता ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान नीलिमा ने, 200 मीटर दौड़ में पंकज नरवर प्रथम व वासुदेव कवड़े ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन धनंजय सिंह ठाकुर द्वारा व आभार तनुश्री सोनी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित सुजीत इवने, रवि कुमार इवने, कृष्ण राव मालवी, महादेव पाल, नेहा चौहान, मयंक जैन, प्रीति उईके, तनुश्री सोनी, संजना धुर्वे, निलेश मोरले, कमल इवने सहित बड़ी संख्या में पीटीआई शिक्षक और युवा मंडल खिलाड़ी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

जिला समन्वय समिति गठित कर नोडल एवं लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किए गए

नर्मदापुरम (निप्र)। भारत सरकार, गृह मंत्रालय के जनगणना कार्य निदेशालय, भोपाल (मध्यप्रदेश) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिला स्तर पर जनगणना कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की गई हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय जनगणना कार्य निदेशालय, भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना द्वारा जिला स्तर पर समस्त जनगणना कार्य के लिए अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार जैन को नोडल एवं लाइजनिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त संबंध में कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी नर्मदापुरम द्वारा जिला जनगणना समन्वय समिति का गठन कर जिला जनगणना अधिकारी को संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण एवं जिला जनसंपर्क अधिकारी नर्मदापुरम को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

नवीन न्यायालय भवन में स्तनपान कक्ष का उद्घाटन, महिलाओं को मिलेगी सुविधा

विदिशा (निप्र)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेख सलीम द्वारा आज नवीन न्यायालय भवन में स्तनपान कक्ष का फीता काट कर विधिवत उद्घाटन किया है। यह पहल न्यायालय परिसर में आने वाली महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस कक्ष के निर्माण का उद्देश्य उन महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गोपनीय स्थान उपलब्ध कराना है, जिनके शिशु छोटे हैं और जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान कराने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। अब महिला कर्मचारी, महिला पक्षकार एवं महिला अधिवक्ता इस विशेष कक्ष का उपयोग कर अपने शिशुओं को सहज रूप से स्तनपान करा सकेंगी। उद्घाटन अवसर पर न्यायालय के समस्त न्यायाधीशगण, न्यायिक अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। इस सुविधा को न्यायालय परिसर में महिला हितैषी वातावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय प्रशासन द्वारा बताया गया कि भविष्य में भी न्यायालय परिसर में नागरिक सुविधाओं के विस्तार हेतु ऐसे प्रयास जारी रहेंगे, जिससे सभी वर्गों को बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सके।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत लक्ष्मी का निःशुल्क हुआ गर्भाशय निष्कासन का ऑपरेशन

बैतूल (निप्र)। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत श्रीमती लक्ष्मी डाकरे के गर्भाशय निष्कासन का निःशुल्क सफल ऑपरेशन हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि श्रीमती लक्ष्मी पति श्री कैलाश डाकरे उम्र 40

निवासी कलारीपथ बंदी इटारसी को लगभग 1 वर्ष से अधिक रक्तस्त्राव की शिकायत थी। श्रीमती लक्ष्मी के परिजन द्वारा निजी चिकित्सक से उपचार कराया गया, किन्तु कोई फायदा न मिलने पर जिला चिकित्सालय बैतूल में स्त्री रोग चिकित्सक पीजीएमओ डॉ रूपल श्रीवास्तव से जांच कराई गई। डॉ.रूपल श्रीवास्तव ने जांच उपरांत सोनोग्राफी की सलाह दी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखने के पश्चात उन्होंने श्रीमती लक्ष्मी को गर्भाशय के ऑपरेशन कराने की सलाह दी। जिला चिकित्सालय में 5 जनवरी 2026 को भर्ती कर 7 जनवरी 2026 को डॉ रूपल श्रीवास्तव द्वारा श्रीमती लक्ष्मी के गर्भाशय का निःशुल्क ऑपरेशन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत किया गया। श्रीमती लक्ष्मी डाकरे को 16 जनवरी को डिस्चार्ज किया गया। अब वह स्वस्थ है। श्रीमती लक्ष्मी के परिजनों ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत निःशुल्क मिले उपचार के लिए शासन का आभार व्यक्त किया है।

रायसेन में सांसद खेल महोत्सव का समापन : केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा

खेल महाकुंभ बनेगा आनंद और प्रेम का पर्व

रायसेन (निप्र)। विदिशा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन कार्यक्रम का सोमवार को रायसेन स्थित खेल स्टेडियम में केन्द्रीय कृषि मंत्री और विदिशा सांसद श्री शिवराज सिंह चौहान, विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नारायण सिंह पंवार और भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑल राउंडर खिलाड़ी श्री रविन्द्र जडेजा द्वारा कन्यापूजन और दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री श्री करन सिंह, खेल एवं सहकारिता विभाग मंत्री श्री विश्वास सारंग, बैतूल विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल, सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी सहित विदिशा संसदीय क्षेत्र के विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा, पूर्व कैबीनेट मंत्री श्री रामपाल सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधी भी उपस्थित रहे।

शुभारंभ के उपरांत अतिथियों द्वारा खुले वाहन में मैदान का भ्रमण किया और खिलाड़ियों व दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। खेल महोत्सव के फाइनल में क्रिकेट-कबड्डी खेलों के फाइनल रोमांचक मुकाबले हुए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि जडेजा यानी जज़्बा, जुनून और जीत की पारी का जश्न है। जो अपनी स्पिन से बल्लेबाज़ को क्लीन बोल्ड कर दे, जो आख़री ओवर में भी जीत की

उम्मीद जगा दे और जो गेंदबाज़ी, बल्लेबाज़ी और फील्डिंग तीनों में कमाल कर दे, वही असली ऑलराउंडर होता है और युवाओं के लिए प्रेरणा है।

केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि रायसेन में आयोजित यह आयोजन केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि आनंद, प्रेम और स्नेह का कुंभ है। यह खेल महाकुंभ 100 दिन पहले प्रारंभ हुआ, जिसमें 952 पंचायतों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि पंचायत, मंडल और विधानसभा स्तर के मुकाबलों के बाद आज क्रिकेट और कबड्डी खेलों में महिला और पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए।

इस पूरे आयोजन में लगभग 1 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें बच्चों के साथ-साथ कहीं सास-बहू ने टीम बनाकर रस्साकशी की तो कहीं मां-बेटी की टीम ने खेलों में हिस्सा लिया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रायसेन किले तक रोपवे की अनुमति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। अब रोपवे किले के ऊपर तक जाएगा और वहां एक भव्य म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही किले का सौंदर्यीकरण कर उसे पर्यटन की दृष्टि से और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे रायसेन की ऐतिहासिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रायसेन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जिसकी घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कर चुके है। साथ ही रायसेन में 12, 13 और 14 अप्रैल को किसान कुंभ और किसान मेला आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की मुस्कान ही उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मामा कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव, ग्रामीण और शहरी युवाओं को उनके कौशल का प्रदर्शन करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी लगातार खेलों इंडिया के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका मंशानुरूप ही देश में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष श्री तोमर ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में वृहद स्तर पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया और आज इसका समापन हो रहा हैं। लगभग सौ दिवस तक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है। खेलों का जीवन में बहुत महत्व है! खेल के माध्यम से जीवन में अनुशासन का समावेश होता है। साथ ही टीम भावना भी बढ़ती है। कार्यक्रम में सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आज यहां खेलों का समागम हो रहा है।

अंत्योदय योजना में 35 किलो प्रति परिवार मिल रहा खाद्यान्न

प्रत्येक पात्रता पर्चीधारी परिवार को राशन दुकान से मिल रहा खाद्यान्न

रायसेन (निप्र)। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रदेश की लगभग 5.37 करोड़ अबादी को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न दिया जा रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रत्येक पात्रता पर्चीधारी परिवार को राशन दुकान से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा ''वन नेशन-वन राशन कार्ड'' अन्तर्गत प्रदेश एवं देश की किसी भी उचित मूल्य दुकान से बायोमेट्रिक सत्यापन/ओटीपी/नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश के 15 लाख से अधिक पात्र परिवारों द्वारा पोर्टेबिलिटी से अपनी सुविधा अनुसार अन्य दुकान से प्रतिमाह राशन प्राप्त किया जा रहा है। पात्र परिवारों को पूरे माह उचित मूल्य दुकान से राशन का वितरण किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पात्र परिवारों की पहचान सुनिश्चित करने एवं वास्तविक गरीब परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने तथा अपात्र एवं 2 बार नाम वाले हितग्राहियों को हटाकर नवीन हितग्राहियों को लाभांवित करने के लिये ईकेवायसी करना अनिवार्य किया गया है। इसमें 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को छोडकर, पात्र हितग्राहियों के ईकेवायसी उचित मूल्य दुकान पर लगाई गई पीओएस मशीन के साथ ही भारत सरकार के मेरा ईकेवायसी मोबाईल ऐप से हितग्राही के फेस अथेंटिकेशन द्वारा किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 29 पात्रता श्रेणी के अंतर्गत नवीन हितग्राहियों को जोड़ने की कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है। इन नवीन आवेदकों द्वारा पीओएस मशीन/फेस अथेंटिकेशन से ईकेवायसी के बाद 3 दिवस की अवधि में पात्रता पर्ची जारी करने की व्यवस्था की गई है। विगत एक वर्ष में लगभग 20 लाख नवीन हिग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। हितग्राही द्वारा ईकेवायसी कराने के बाद पात्रता पर्ची जारी की जा रही है। किसी भी पात्रता पर्चीधारी परिवार का राशन रोकने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिये गए हैं।

कैंप आयोजित कर स्वरोजगार योजनाओं में हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत व वितरित कराएं : कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी

पीएम श्रम योगी मानधन योजना में प्रगति नहीं लाने पर श्रम पदाधिकारी के वेतन काटने के निर्देश

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत एवं लाभ वितरित किए जाएं। यह निर्देश उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान दिए।

बैठक में पीएम श्रम योगी मानधन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने योजना अंतर्गत पंजीयन में संतोषजनक प्रगति नहीं पाए जाने पर श्रम पदाधिकारी के वेतन काटने के निर्देश दिए। बताया गया कि पेंशन योजना के प्रथम चरण में शहरी क्षेत्र में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक पंजीयन अभियान चलाया जा रहा है, जबकि द्वितीय

चरण में ग्रामीण क्षेत्र में 15 फरवरी से 15 मार्च 2026 तक अभियान संचालित किया जाएगा। योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक, सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले मजदूर, घरेलू कामगार, किसान आदि श्रमिक ले सकते हैं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना की समीक्षा करते हुए योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर उप संचालक उद्यानिकी को अप्रसन्नता पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल सर्टिफाइड कार्य में प्रगति नहीं होने पर कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण, एएनसी पंजीयन में कम प्रगति पाए जाने पर सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन को तथा सीएम हेल्पलाइन में संतोषजनक प्रगति नहीं लाने पर जिला आबकारी अधिकारी को भी अप्रसन्नता पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने नल-जल योजनाओं के निरीक्षण कर हर घर जल सर्टिफिकेशन एवं हैंडओवर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। बैठक में लंबित नामांतरण प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सभी राजस्व अधिकारियों को प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। नवीन एवं लंबित वन अधिकार दावों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (वन) को प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर पट्टों का वितरण सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा में जल संसाधन विभाग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वाणिज्यिक कर, श्रम, सामाजिक न्याय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन विभाग को शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संकल्प से समाधान अभियान की समीक्षा कर सभी विभागों को अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, अपर कलेक्टर श्रीमती वंदना जाट सहित समस्त विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएमएचओ ने ली स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक

हाई रिस्क गर्भवतियों पर विशेष फोकस

विदिशा (निप्र)। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रामहित कुमार द्वारा आज गंज बासौदा के जनपद सभा कक्ष में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमेन्द्र तिवारी, जन चिकित्सालय बासौदा के प्रभारी अस्पताल सह अधीक्षक डॉ. रविन्द्र चिड़ार सहित बीईई, बीपीएम, बीसीएम, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सेक्टर सुपरवाइजर, सीएचओ, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा सुपरवाइजर एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में सीएमएचओ ने क्षेत्रवार आशा, एएनएम और सीएचओ से गर्भवती महिलाओं की अद्यतन जानकारी ली। अप्रैल से अब तक किए गए पंजीयन, हाई रिस्क गर्भवतियों की संख्या तथा उनके प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से पूछा कि हाई रिस्क गर्भवतियों की देखरेख में वे क्या भूमिका निभा रहे हैं और क्या प्रयास किए जा रहे हैं।

सभी आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि चिन्हित हाई रिस्क गर्भवतियों को प्रसव तिथि से सात दिन पूर्व बर्थ वेटिंग रूम में भर्ती कराना सुनिश्चित करें। साथ ही समय पर 108 एम्बुलेंस सेवा का उपयोग करने के निर्देश दिए गए, ताकि घर या रास्ते में प्रसव की स्थिति से बचा जा सके और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। परिवार नियोजन की समीक्षा करते हुए आशाओं से उनके क्षेत्र के लक्ष्य दंपत्तियों एवं अपनाए जा रहे साधनों की जानकारी ली गई। आशा डायरी का अवलोकन कर कार्य प्रोटोकॉल के पालन के निर्देश दिए गए। निष्क्रिय आशाओं के विरुद्ध सेवा समाप्ति का प्रस्ताव भेजने की बात भी कही गई। बैठक के दौरान इस माह प्रसव संभावित गर्भवतियों से फोन पर संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली गई। शत-प्रतिशत प्रसूताओं एवं नवजात शिशुओं की एचबीएनसी एवं एचबीवाईसी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निमोनिया, दस्त, संक्रमण, स्तनपान और कम वजन संबंधी जांच प्रोटोकॉल अनुसार करने तथा हाई रिस्क पाए जाने पर उच्च स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करने के निर्देश दिए गए। सीएचओ को डीएसएस पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने को कहा गया। एएनएम एवं सीएचओ को गर्भवती महिलाओं का शीघ्र पंजीयन, चार अनिवार्य जांच, टीकाकरण तथा यू-विन पोर्टल पर एंट्री करने के निर्देश दिए गए। मॉडरेट एनीमिक गर्भवतियों को आयरन सुक्रोज एवं पीएचसी/सीएचसी स्तर पर एफसीएम उपचार दिलाने पर जोर दिया गया, जिससे हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार हो सके। सीएमएचओ ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के कार्यों का नियमित निरीक्षण करने और सभी गतिविधियों की शत-प्रतिशत पोर्टल एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर ने स्कूलों व छात्रावासों का औचक निरीक्षण, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज शहर के विभिन्न शासकीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय परिसरों का भ्रमण करते हुए शैक्षणिक एवं भौतिक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। कलेक्टर ने कक्षाओं में पहुंचकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया और पढ़ाई, उपलब्ध सुविधाओं तथा विद्यालयीन वातावरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति, कक्षाओं के संचालन, भवनों की स्थिति तथा मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। कक्षाओं के नियमित एवं प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिला परियोजना समन्वयक को शिक्षण व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए। टीला खेड़ी स्थित विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष एवं प्रयोगशाला का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर ने उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण अध्यापन कार्य नियमित रूप से संचालित करने के स्पष्ट निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक सुधारात्मक कार्य समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की विभागीय गतिविधियों की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल बैठक में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा संकल्प से समाधान अभियान, विभागीय गतिविधियों तथा योजनाओं एवं सीएम हेल्पलाईन की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने जिले में संकल्प से समाधान अभियान के तहत शिविरों के आयोजन और आवेदनों के निराकरण की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी हितग्राही शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। कलेक्टर श्री विश्कवर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे शिविरों में स्वयं उपस्थित रहें तथा विभाग से संबंधित आवेदनों को गंभीरतापूर्वक शीघ्रता से निराकृत कराते हुए पोर्टल पर अपलोड कराएं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि संकल्प से समाधान अभियान नागरिकों की समस्याओं के समाधान

और योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि अभियान के तहत सांची जनपद क्षेत्र में अभी तक प्राप्त 8876 आवेदनों में से 3312 आवेदन निराकृत हो गए हैं। इसी प्रकार बाड़ी जनपद क्षेत्र में प्राप्त 8285 आवेदनों में से 7625 आवेदन, उदयपुरा जनपद क्षेत्र में प्राप्त 5776 आवेदनों में से 5196 आवेदन, औबेदुल्लागंज जनपद क्षेत्र में प्राप्त 4012 आवेदनों में से 2587 आवेदन, सिलवानी जनपद क्षेत्र में प्राप्त 3370 आवेदनों में से 2828 आवेदन, बेगमगंज जनपद क्षेत्र में प्राप्त 2922 आवेदनों में से 2025 आवेदन और गैरतगंज जनपद क्षेत्र में प्राप्त 2580 आवेदन में से 1808 आवेदन निराकृत हो गए हैं। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने शेष आवेदनों को भी शीघ्र निराकृत कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान सभी एसडीएम और खनिज अधिकारी को क्षेत्र में खनिज सम्पदा का अवैध उत्खनन या परिवहन होने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि अवैध उत्खनन या परिवहन पर सख्ती से रोक लगाएं। उन्होंने गीता भवनों के लिए भूमि आवंटन कार्य, पीएम आवास योजना शहरी, पीएम स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी लेते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार एक बगिया मॉ के नाम परियोजना के तहत जनपद पंचायतवार फलोद्यान बगिया में रोपित पौधों के जीवित होने की जानकारी ली। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने उप संचालक कृषि को स्प्रिंगलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही नरवाई प्रबंधन हेतु किसानों को जागरूक करने के साथ ही हैप्पी सीडर, सुपर सीडर सहित अन्य उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा। उन्होंने एसडीएम तथा कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि बिना स्ट्रामेनेजमेंट के हार्वेस्टर चलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाईन प्राप्त होते ही नियमानुसार निराकरण की कार्यवाही की जाए। कोई भी शिकायत अधिक समयावधि तक लंबित ना रहे। उन्होंने कुछ विभागों की सीएम हेल्पलाईन नॉन अटेन्डेन्ट रहने पर नाराजगी व्यक्त कर संबंधितों को गंभीरतापूर्वक कार्य करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय, सहाय कलेक्टर श्री कुलदीप पटेल तथा अनेक विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

दलहन क्षेत्र का राष्ट्रीय सम्मेलन 7 फरवरी को सीहोर के अमलाहा में

दलहन क्षेत्र में नीति निर्धारण और अनुसंधान में मील का पत्थर होगा साबित : कृषि मंत्री कंषाना

भोपाल(नप्र)। प्रदेश के अमलाहा, जिला सीहोर में 7 फरवरी को दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श के लिये एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन में दलहन क्षेत्र की मूल संवेदनाओं, वर्तमान चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में देश के प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारीगण, दलहन अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक, सरकारी बीज उत्पादक संस्थाएँ, दाल उद्योग से संबंधित प्रतिनिधि एवं अन्य सहयोगी एजेंसियाँ भाग लेंगी। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि दलहन उत्पादन को सुदृढ़ करने, किसानों की आय बढ़ाने तथा उन्नत तकनीकों के माध्यम से उत्पादकता सुधार पर अपने विचार साझा करेंगे। यह सम्मेलन दलहन क्षेत्र में नीति निर्धारण और अनुसंधान में मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन का उद्देश्य किसानों तक नवीन शोध, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक खेती पद्धतियों तथा बाज़ार से जुड़ी जानकारी पहुँचाना है, जिससे दलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। साथ ही विभिन्न राज्यों के अनुभवों के आदान-प्रदान से राष्ट्रीय स्तर पर दलहन विकास की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की जाएगी।

मां की तेरहवीं के बाद बेटे ने किया सुसाइड

बेटी के प्रेम विवाह किए जाने से भी दुखी था, भोपाल पुलिस ने शुरू की जांच

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बिलखिरिया इलाके में रहने वाले एक अधेड़ ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मंगलवार दोपहर को मां की तेरहवीं का कार्यक्रम था। इसके समाप्त होने के बाद रात को उन्होंने जान दे दी। इसी के साथ उनकी बेटी ने भी कुछ समय पहले परिजनों की मर्जी के बगैर लव मैरिज कर ली। जिसकी वजह से वह तनाव में चल रहे थे। पुलिस का मानना है कि इन्हीं कारणों के चलते अधेड़ ने सुसाइड किया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

बिलखिरिया थाना क्षेत्र निवासी 55 वर्षीय दशरथ प्रायवेट ड्रायवरी करता था। पिछले दिनों उसकी माताजी का निधन हो गया था। दशरथ को लगता था कि उसकी बेटी द्वारा कुटुम्ब के लड़के से ही शादी कर लेने के सदमे से ही मां का निधन हुआ है। मंगलवार को तेरहवीं कार्यक्रम था। दिन में ब्राह्मणों को भोज कराने के बाद रात में उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया।

रिश्ते के भाई से बेटी ने की थी शादी- घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचनामा बनाकर कार्रवाई शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि करीब तीन महीने पहले उनकी बेटी ने अपने रिश्ते के भाई से शादी कर ली थी।

परिजनों की समझाईश रही थी बेअसर

शादी से पहले परिजनों और रिश्तेदारों ने बेटी को काफी समझाईश दी थी, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और मर्जी से शादी कर ली। उसके बाद से पिता तनाव में थे। अनुमान है कि इसी तनाव के चलते उन्होंने फांसी लगाई होगी। बुधवार दोपहर को पीएम के बाद बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

महिला नायब तहसीलदार ने किसानों से कहा दूर हटो और तमीज से बात करो...

किसान भड़के, बोले-वापस जाओ

ग्वालियर (नप्र)। मौसम की मार बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे करने पहुंची महिला नायब तहसीलदार और किसानों के बीच बहसबाजी हो गई। ग्वालियर के भितरवार में वे गाड़ी से उतरीं तो किसान पास पहुंच गए, उन्होंने दूर हटने के लिए बोला तो बहसबाजी होने लगी। किसानों से उनसे साफ कह दिया कि बात नहीं करना तो आप वापस जाईए। जानकारी अनुसार ग्वालियर में मंगलवार की सुबह हुई ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई।

इन बर्बादी फसलों का सर्वे करने के लिए जब महिला नायब तहसीलदार मौके पर पहुंची तो उनकी किसानों से झड़प हो गई। यह पूरा घटनाक्रम भितरवार इलाके के कछुआ गांव का है।

दरअसल मंगलवार की अल सुबह भितरवार इलाके के गांव में ओलावृष्टि हुई थी। इस वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर प्रशासनिक अमला ओलावृष्टि वाले इलाकों में सर्वे करने के लिए पहुंचा था।

किसानों से दूर हटने को कहा तो बहस होने लगी- भितरवार के कछुआ गांव में जब महिला नायब तहसीलदार पूजा मावई अपने अमले के साथ पहुंची तो यहां गाड़ी से उतरते ही उनकी किसानों से बहस शुरू हो गई। महिला नायब तहसीलदार ने किसानों को दूर हटने के लिए कहा तो किसान भी नाराज हो गए और उन्होंने नायब तहसीलदार को वापस जाने तक के लिए कह दिया।

एसडीएम मौके पर पहुंचे और स्थिति संभाली- मामला बिगड़ते देख एसडीएम राजीव समाधिया मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को काबू में किया। इसके साथ ही एसडीएम ने सभी किसानों को भरोसा दिया की सर्वे अच्छी तरह से किया जाएगा और जिन किसानों का जितना नुकसान हुआ है उतना मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके बाद किसान शांत हुए।

अज्ञात चारपहिया वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, दो भाइयों की मौत

छिंदवाड़ा (नप्र)। छिंदवाड़ा के हर्रई थाना क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जुंगावानी टोल प्लाजा के पास बागदेव घाटी में अज्ञात चारपहिया वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक सुरलाखापा निवासी विक्रम गोस्वामी अपने रिश्ते के भाई आकाश गोस्वामी के साथ अमरवाड़ा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अमरवाड़ा सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान विक्रम गोस्वामी (पिता हुकम) और आकाश गोस्वामी (पिता अमरसिंह) ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही हर्रई थाना प्रभारी ओमेश मार्को मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में उद्योग भवन में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सौजन्य मुलाकात की।

सुदृढ़ हो रही हैं मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएँ : सीएम यादव

बेहतर स्वास्थ्य संकेतकों की ओर तेज गति से अग्रसर हो रहा है मप्र

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आम नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिये मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सशक्त किया जा रहा है। समन्वित प्रयासों से स्वास्थ्य अधोसंरचना का व्यापक विस्तार हुआ है और आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। मेडिकल शिक्षा, सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं, मातृ-शिशु स्वास्थ्य एवं जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों में उल्लेखनीय प्रगति के साथ मध्यप्रदेश स्वास्थ्य संकेतकों में निरंतर सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

मातृ-शिशु स्वास्थ्य में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। प्रदेश में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 173 से घटकर 142 तथा शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 41 से घटकर 37 हुई है। जननी सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत लाखों लाभार्थियों को हजारों करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है। नवजात एवं कुपोषण प्रबंधन में एसएनसीयू एवं एनआरसी की सफल डिस्चार्ज दरों में भी वृद्धि हुई है।

जनस्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 5 प्रदर्शनकारी राज्यों में शामिल हुआ है। सिकल सेल मिशन के अंतर्गत व्यापक स्क्रीनिंग एवं उपचार सुविधाएँ विकसित की गई हैं। आयुष्मान भारत योजना में 4.43 करोड़ कार्ड तैयार कर प्रदेश के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। योजनांतर्गत पात्र परिवारों को 5 लाख रूपये तक निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। साथ ही गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में त्वरित रूप से उच्च स्तरीय उपचार पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से मुहैया कराया जा रहा है। अब तक 120 से अधिक नागरिकों को आपात स्थिति में सेवा का लाभ मिला है। मानवीय संवेदनाओं के दृष्टिगत निःशुल्क एवं सम्मानजनक शव-परिवहन सेवा भी प्रारंभ की गई है। राह-वीर योजना में आपात काल में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने वाले नागरिक को 25 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। साथ ही, मोबाइल मेडिकल यूनिटों के माध्यम से दूरस्थ एवं जनजातीय क्षेत्रों में नियमित स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं।

मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर है मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2003 तक प्रदेश में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे। वर्तमान में प्रदेश में 33 मेडिकल कॉलेज है। विगत 2 वर्षों में शासकीय मेडिकल कॉलेजों की संख्या 14 से बढ़कर 19 तथा निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो गई है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, इंदौर में 50 एमबीबीएस सीटों के साथ संचालन प्रारंभ किया गया है। आगामी 2 वर्षों में 6 शासकीय एवं पीपीपी मोड पर 13 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किया जाना योजना में शामिल है। विगत 2 वर्षों में सरकारी एमबीबीएस सीटें 2275 से बढ़कर 2850 हुई हैं, जबकि सरकारी एवं निजी मिलाकर कुल एमबीबीएस सीटें 5550 हो गई हैं। पीजी (एमडी/एमएस) सीटों में भी वृद्धि करते हुए सरकारी पीजी सीटें 1262 से बढ़कर 1468 तथा कुल पीजी सीटें 2862 हो गई हैं। इसके अतिरिक्त 93 सुपर स्पेशियलिटी सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। सशक्त स्वास्थ्य सेवाओं से मध्यप्रदेश मेडिकल हब बनने की ओर अग्रसर है। पीपीपी मॉडल पर कटनी, धार, पन्ना और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना प्रगति पर है। एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, इंदौर में अस्पताल भवन, मिनी ऑडिटोरियम एवं नर्सिंग हॉस्टल जैसे अधोसंरचनात्मक कार्यों हेतु 773.07 करोड़ रूपये के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। श्यामशाह मेडिकल कॉलेज, रीवा के लिए 321.94 करोड़ रूपये तथा सतना मेडिकल कॉलेज से जुड़े नए अस्पताल हेतु 383.22 करोड़ रूपये के कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इसके साथ ही 13 नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए 192.40 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं। आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के अंतर्गत इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में लिनियर एक्स-रेटर मशीनों की स्वीकृति दी गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और सागर में सीटी स्कैन एवं एमआरआई मशीनें स्थापित की गई हैं। भोपाल एवं रीवा में कार्डियक कैथ लैब की स्थापना की गई है।

खाना देने आई 10 वर्षीय भतीजी... चाचा ने किया रेप

एक्सीडेंट में घायल पिता भोपाल में भर्ती, मां भी वहीं थीं

गंजबासौदा(विदिशा)(नप्र)। विदिशा के गंजबासौदा में मंगलवार रात को चाचा ने अपनी 10 साल की भतीजी से रेप किया। बच्ची खाना देने के लिए गई थी। आरोपी चाचा ने बच्ची को पकड़कर झाड़ियों में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना शहर थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के मुताबिक रेप पीड़िता के पिता का एक्सीडेंट हुआ है। वे भोपाल में एडमिट हैं। उसकी मां भी पिता के साथ अस्पताल में ही थी। बच्ची अपने 2 भाइयों के साथ घर में थी। इसी का फायदा उठाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है।

वहीं मामले की जानकारी मिलते ही 4 फरवरी की सुबह रेप पीड़िता की मां भोपाल से विदिशा जिला अस्पताल पहुंची। बेटी से मिलकर थाने पहुंची। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

दरअसल, 1 फरवरी को बच्ची के पिता का एक्सीडेंट हो गया था। पिता को बच्ची की मां भोपाल इलाज कराने ले गई थी। इस दौरान बच्ची घर में अपने 2 भाइयों के साथ थी। 3 फरवरी की रात 9 बजे बच्ची अपने चाचा को खाने देने गई थी। आरोपी और नाबालिग का घर अगल-बगल में है।

इस दौरान चाचा की नीयत बिगड़ गई। बच्ची को पकड़कर घर से बाहर ले गया। घर से बाहर ले जाते वक्त नाबालिग के 12 साल के भाई ने देख लिया। करीब एक घंटे बाद जब बहन नहीं लौटी तो भाई ने झाड़ियों में जाकर देखा, तब तक आरोपी चाचा रेप की वारदात को अंजाम दे चुका था।

आरोपी रात में ही पकड़ा गया

नाबालिग के भाई ने अपने पड़ोसियों को जानकारी दी। पड़ोसियों ने 11 बजे रात शहर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी की तलाश शुरू की। करीब 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने रात को ही आरोपी को गांव के ही खेत से हिरासत में लिया।

शहर पुलिस आरोपी को थाने लेकर आई, जहां पूछताछ की। वहीं रेप पीड़िता को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। इस दौरान प्राथमिक इलाज के बाद बच्ची की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बच्ची की हालत पहले से बेहतर है। बच्ची का इलाज जारी है।

आरोपी आदतन शराबी, पत्नी भी छोड़कर भाग चुकी

मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी आदतन शराबी है। शराब पीने की वजह से आरोपी की पत्नी भी छोड़कर मायके जा चुकी है। आरोपी घर में अकेले ही रहता था। गांव में आए दिन विवाद करते रहता था। अपराधी किस्म का है।

आरोपी से पूछताछ की जा रही- मामले में एसडीओपी शिखा भलावी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में लिया गया है। आरोपी की उम्र 23 साल है। आरोपी से रेप मामले में पूछताछ की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

नाबालिग चोरों ने कूड़े में बनाई थी 'तिजोरी'

कचरे के ढेर से निकले सोने के बिस्किट, चांदी की ईंटें और जेवर

खरगोन (नप्र)। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह में सूने घरों और दुकानों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। हैरान करने वाली बात यह रही कि करीब 90 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और नकदी चोरों ने चोरी के बाद कूड़े के ढेर में छुपा दिए थे। इस हाई-प्रोफाइल चोरी का मास्टरमाइंड एक 16 वर्षीय नाबालिग निकला, जिसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम दिया।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बड़वाह थाना क्षेत्र में जनवरी के अंतिम सप्ताह में एक सूने मकान से बड़ी चोरी और इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से नकदी चोरी की घटनाएं हुई थीं। पुलिस अधीक्षक रवींद्र वर्मा के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने लगातार 48 घंटे तक दर्जनों सीसीटीवी फुटेज खंगाले, संदिग्धों की गतिविधियों को ट्रेस किया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।

जांच के दौरान सीसीटीवी में दिख रहे एक संदिग्ध का हुलिया गोदी पट्टी क्षेत्र के एक नाबालिग से मेल खाता पाया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपने साथियों

हर्ष प्रजापति (22) और दिव्यांश प्रजापति (19) के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 300 ग्राम सोने के बिस्किट, करीब 370 ग्राम सोने के आभूषण, चांदी के पांच ईंटे (पांच किलो), नकदी 28,550 रुपये और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद की।

कचरे के ढेर में छिपाया था सोना-चांदी- पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गिरफ्तार नाबालिग और एक आरोपी पर पहले से चोरी और मारपीट के मामले दर्ज हैं। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि चोरी के बाद पकड़े जाने के डर से उन्होंने कीमती गहनों को कूड़े के ढेर में छुपा दिया था।

जेवरों को लॉकर में नहीं रख पाए थे- बड़वाह की एसडीओपी अर्चना रावत ने बताया कि दरअसल शर्मा और उनकी बहन इवेंट मैनेजमेंट में काम करते हैं और उनके अन्य रिश्तेदार दिल्ली में मेडिकल फील्ड से संबंधित है। वह उनकी मां (रिटायर्ड अधिकारी भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय) की तबीयत खराब रहने के चलते बड़वाह में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, और इसलिए इन जेवरों को लॉकर में नहीं रख पाए थे।

उन्होंने बताया कि 16 वर्षीय मास्टरमाइंड आरोपी रेकी कर सारी इनफॉरमेशन इकट्ठी करता था। दोनों घटनाओं में उसी की प्लानिंग के मुताबिक चोरी की गई थी।

मधुमक्खियों के झुंड का बड़ा हमला

20 बच्चों के लिए आंगनबाड़ी कुक ने दे दी अपनी जान

नीमच (नप्र)। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक आंगनवाड़ी कुक ने 20 बच्चों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। कुक का नाम कंचन बाई मेघवाल है। वह जिले के माधवाड़ा पंचायत स्थित रानपुर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत थीं। बच्चों के खेलने के दौरान मधुमक्खियों का बड़ा झुंड उन पर हमला कर दिया। मगर कंचन बाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना, बच्चों की जान बचाई हैं।

कंचन बाई ने बच्चों को बचाया- दरअसल, सोमवार को मधुमक्खियों के झुंड ने जब कंचन बाई पर हमला किया तो वह बच्चों को बचाने में जुट गईं। कुक कंचन बनाई ने बच्चों को बचाने के लिए तिरपाल और चटाई का इस्तेमाल किया। उन्होंने बच्चों को उसमें लपेटा और आंगनबाड़ी के अंदर ले गईं। बच्चों को बचाने के दौरान मधुमक्खियों ने कंचन बाई मेघवाल पर हमला कर दिया। साथ ही उन्हें सैकड़ों डंक मारे हैं।

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया- वहीं, मधुमक्खियों ने कंचन बाई मेघवाल स्कूल में ही बेहोश होकर गिर पड़ीं। गांव के लोग घटना के बारे में सुनकर वहां पहुंचे तो वह बेहोश पड़ी थीं। सूचना पर कॉन्स्टेबल कालूनाथ और पायलट राजेश राठौर भी पहुंचे। साथ ही उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके शरीर पर मधुमक्खी के अनगिनत

डंक थे। यह इस बात की गवाही थी कि उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए बहादुरी दिखाई है।

बच्चों के लिए खाना बनाती थीं कंचन बाई- कंचन बाई मेघवाल रानपुर गांव के लिए एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से ज्यादा बढ़कर थीं। वह बच्चों के लिए दोपहर का खाना भी बनाती थीं। साथ ही जय माता दी सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष भी थीं। साथ ही परिवार में अकेले कमाने वाली थीं। उनका पति शिवलाल लकवाग्रस्त हैं। साथ ही एक बेटा और दो बेटियां हैं। मंगलवार को शव जब पीएम के बाद पहुंचा तो पूरा गांव नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा था। ऐसे में उनकी बहादुरी शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। गौरतलब है कि घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। गांव में मात्र एक ही हैंडपंप है। उसी हैंडपंप के पास मधुमक्खियों ने अटैक भी किया था। ऐसे में डर के मारे लोग वहां तक पानी लेने भी नहीं जा रहे हैं।

महाशिवरात्रि के लिए दर्शन व्यवस्था तय, 10 लाख भक्त आएंगे

आम श्रद्धालुओं को डेढ़ और पासधारियों को एक किमी पैदल चलना पड़ेगा

उज्जैन (नप्र)। महाशिवरात्रि महापर्व 2026 (15 फरवरी) पर भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस अवसर पर सामान्य श्रद्धालुओं को लगभग डेढ़ किलोमीटर और 250 रुपए की शीघ्र दर्शन रसीद या पासधारी श्रद्धालुओं को करीब एक किलोमीटर पैदल चलने के बाद भगवान महाकाल के दर्शन होंगे।

भक्तों को सुलभ और सुरक्षित दर्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भस्म आरती दर्शन, लड्डू प्रसाद, पूछताछ केंद्र, पार्किंग, जूता स्टैंड, पेयजल, प्रकाश, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर मंदिर परिसर में अहम बैठक आयोजित की गई। जिसमें कई निर्णय लिए गए। बैठक में कलेक्टर एवं मंदिर प्रशासक रौशन सिंह, प्रथम कौशिक, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा, निगम आयुक्त अभिलाष मिश्र, सहायक प्रशासक आशीष फलवाडीया सहित मंदिर समिति के अधिकारी मौजूद रहे।

सामान्य श्रद्धालुओं की प्रवेश-निर्गम व्यवस्था

सामान्य श्रद्धालु भील समाज धर्मशाला के समीप बने द्वार से प्रवेश करेंगे। वे भील समाज धर्मशाला, चारधाम मंदिर पार्किंग, शक्ति पथ, त्रिवेणी संग्रहालय के समीप, नंदी द्वार, श्री महाकाल महालोक, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर-01, टनल, नवीन टनल-01 होते हुए गणेश मंडपम से भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के बाद श्रद्धालु आपातकालीन निर्गम द्वार से बाहर निकलकर बड़ा गणेश मंदिर, हरसिद्धि मंदिर चौराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

शीघ्र दर्शन व पासधारी श्रद्धालुओं की व्यवस्था

शीघ्र दर्शन 250 रुपए टिकटधारी श्रद्धालुओं के लिए अलग से बैरिकेटिंग की गई है। ये श्रद्धालु भील समाज धर्मशाला, चारधाम मंदिर पार्किंग, अशोक सेतु, मानसरोवर भवन, फेसेलिटी सेंटर-01, टनल, नवीन टनल-01 होते हुए गणेश मंडपम से दर्शन करेंगे। इसके अलावा शीघ्र दर्शन टिकटधारी श्रद्धालु हरसिद्धि पाल पार्किंग, बड़ा गणेश गली, प्रीपेड बूथ तिराहा, शहनाई जिगजेग, द्वार क्रमांक-01 से मंदिर में प्रवेश कर दर्शन कर सकेंगे।

भस्म आरती दर्शन व्यवस्था

महाशिवरात्रि पर्व पर भस्म आरती के लिए पंजीयनधारी श्रद्धालुओं का प्रवेश मानसरोवर भवन और द्वार क्रमांक-01 से निर्धारित किया गया है।

पार्किंग सुविधा के लिए

पार्किंग- सामान्य श्रद्धालु के लिए कर्कराज पार्किंग, मेघदूत पार्किंग में व्यवस्था की गई है। शीघ्र दर्शन टिकटधारी श्रद्धालुओं के लिए कार्तिक मेला ग्राउंड, राणौजी की छत्रि, शगुन गार्डन, महाकाल मंडपम् पर व्यवस्था की गई है।

जूता स्टैंड- सुविधा के लिए भील समाज धर्मशाला, झालरिया मठ एवं हरसिद्धि पाल पर व्यवस्था की गई।

शीघ्र दर्शन काउंटर- कर्कराज पार्किंग, हरसिद्धि पाल पार्किंग पर की जाएगी।

लड्डू प्रसाद- काउंटरों की व्यवस्था नृसिंहघाट रोड पर एवं हरसिद्धि रोड पर की जाएगी।

प्रशासन की अपील- मंदिर समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें, सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें और धैर्य बनाए रखें, जिससे सभी भक्त सुचारू रूप से भगवान महाकाल के दर्शन कर सकें।